



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236904
CG-DL-E-29062022-236904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2022/आषाढ़ 8, 1944

No. 165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2022/ASHADHA 8, 1944

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

मामला सं. एडी(ओआई) 10/2021

विषय: बंगलादेश और थाईलैंड से क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

सं. 6/10/2021—डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” या “एडी नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. पृष्ठभूमि

- मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स साइसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सेंट-गोबेन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड (इसके बाद इन्हें “घरेलू उद्योग” या “आवेदक” या “याचिकाकर्ता” भी कहा गया है) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक

आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें बंगलादेश और थाइलैंड (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/10/20121-डीजीटीआर दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई, ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी को उक्त नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें बंगलादेश और थाइलैंड से ‘क्लियर फ्लोट ग्लास’ के पाटन का आरोप लगाया गया था।
 - ख. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30.6.2021 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - घ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
 - ङ. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति भेजी।
 - च. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई।
 - छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
 - (i) पीएचपी फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज, बंगलादेश
 - (ii) उस्मानिया ग्लास शीट फैक्ट्री लिमिटेड, बंगलादेश
 - (iii) नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलादेश
 - (iv) कबिनबुरी ग्लास इंडस्ट्री, थाइलैंड
 - (v) एजीसी एसिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, थाइलैंड
 - ज. बंगलादेश से केवल नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएफजीआईएल), और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनजीआईएल) द्वारा निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया गया। अन्य किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियां भेजी:
- क. एटलान्टिक ट्रेडिंग-मुंबई
- ख. कांचघर - मुंबई
- ग. फिशफा ग्लास - मुंबई
- घ. स्मार्थ इंडस्ट्रीज - मुंबई
- ङ. पारशनाथ ट्रेडिंग - मुंबई
- च. आसमी ट्रेडर्स - मुंबई
- छ. रजत ग्लास ट्रेडर्स - कराड
- ज. चंदन ग्लास ट्रेडर्स - पुणे
- झ. कोचर ग्लास ट्रेडर्स - भोपाल
- ञ. गनेरीवाला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड - कोलकाता
- ट. स्योर सेफ ग्रुप/गनेरीवाला ग्लास ट्रेडर्स - कोलकाता
- ठ. एमएस ग्लास ट्रेडर्स - कोलकाता
- ड. ग्लेज आर्चिटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड - कोलकाता
- ढ. ग्लेज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड - कोलकाता
- ण. सराफ ग्लास प्राइवेट लिमिटेड - कोलकाता
- त. जीएससी - नोएडा
- थ. शिव शक्ति - रुड़की
- द. रिद्धि सिद्धि - जयपुर
- ध. बनारस ग्लास - लखनऊ
- न. टी.एल. वर्मा - चंडीगढ़
- प. जगदम्बा ग्लास - दिल्ली
- फ. शीश महल टफ - रोहतक
- ब. नूतन ग्लास एचएस (प्राइवेट) लिमिटेड - बैंगलौर
- भ. महावीर ग्लास एचएस - बैंगलौर
- म. कर्नाटका मेटल कंपनी - बैंगलौर
- य. इम्पेक्ट सेफ्टी ग्लास (प्राइवेट) लिमिटेड - बैंगलौर
- कक. साउदर्न ऑटो प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड - बैंगलौर
- खख. टफ ग्लास इंडिया - बैंगलौर
- गग. येशो फ्लोट ग्लास (प्राइवेट) लिमिटेड - हैदराबाद
- घघ. भंडारी ग्लास कंपनी - हैदराबाद
- ङ.ड. प्रकाश ग्लास - हैदराबाद
- चच. महावीर ग्लास - चेन्नई

- छछ. महावीर मिरर – विशाखापट्टनम
- जज. उमा इंडस्ट्रीज – बेंगलोर
- झझ. जय मिरर इंडस्ट्रीज – चेन्नई
- ज. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ता संघों ने अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत दिया है:
- (i) मैसर्स अयुर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स के.के. एंटरप्राइज
 - (iii) मैसर्स आशा
 - (iv) फैडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी)
- ट. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 माह) की है तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 – अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्य/अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम्स, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। चर्चा के दौरान, यह नोट किया गया था कि निर्यातकों ने एक बीजक विशेष के अन्तर्गत विभिन्न मोटाई के फ्लोट ग्लास का निर्यात किया है। तथापि, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में केवल एक मोटाई शीर्ष के अन्तर्गत उस बीजक की समूची मात्रा की सूचना दी गई है। इससे भारत को उनके निर्यातों की सीआईएफ कीमतें प्रभावित हुई हैं। डीजी-सिस्टम्स के आंकड़ों और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के विश्लेषण के बाद, निर्यातकों के अनुरोध में वास्तविकता पाई गई कि इसके मद्देनजर सौदों की जांच और अपेक्षित विश्लेषण के बाद आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजी-सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया गया है ताकि विशिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा को उससे जोड़ा और व्यवहार्य सीमा तक प्रस्तुत उत्तरों की वैधता का सत्यापन किया जा सके।
- ढ. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।
- ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 22.11.2021 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, जिसमें विभिन्न पक्षकारों ने भाग लिया। यह मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से उन विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार उनके खंडन प्रस्तुत कर सकें।
- त. आवेदकों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और भारत में संबद्ध वस्तु के निर्माण व बिक्री की लागत और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

- द. घरेलू उद्योग और सहयोगी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना का मौके पर सत्यापन के माध्यम से आवश्यक सीमा तक वास्तविक निरीक्षण किया गया था। आवश्यक सुधार के बाद जहां लागू हो, केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।
- ध. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के साक्ष्यों से उनके समर्पित होने और वर्तमान जांच से संगत समझी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- न. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है, की सत्यता से संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों/दस्तावेजों का संगत और संभव सीमा तक सत्यापन किया है।
- प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- फ. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण, जो अंतिम जांच परिणाम के आधार पर बनता, हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए दिनांक 15.06.2022 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन विवरण पर टिप्पणियों के संबंध में इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में जहां तक संगत पाया गया है, विचार किया गया है।
- ब. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां ऐसे पक्षकार को प्राधिकारी ने असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- भ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना दर्शाता है।
- म. संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.02 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को बंगलादेश और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4 एमएम से 12 एमएम (दोनों शामिल हैं) के रेंज के नॉमिनल मोटाई के “क्लियर फ्लोट ग्लास” के रूप में परिभाषित किया गया है, नामिल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है।

क्लियर फ्लोट ग्लास का प्रयोग निर्माण, रेफ्रिजरेशन, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में होता है। यह उत्पाद ग्लास की एक उच्चतर गुणवत्ता है। इसकी अंतरनिहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, डिस्टोरशन मुक्त समतल सतह आदि के कारण इस उत्पाद के प्रयोग विभिन्न रूप से बढ़ते जा रहे हैं।

फ्लोट ग्लास को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लासवेयर” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ शीर्षों 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को 4 एमएम से 12 एमएम (दोनों शामिल हैं) के रेंज के नॉमिनल मोटाई के “क्लियर फ्लोट ग्लास” के रूप में परिभाषित किया गया है, नॉमिनल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है।
7. क्लियर फ्लोट ग्लास का प्रयोग निर्माण, रेफ्रिजरेशन, दर्पण, सौर ऊर्जा उद्योग आदि में होता है। यह उत्पाद ग्लास की एक उच्चतर गुणवत्ता है। इसकी अंतरनिहित मजबूती, उच्च ऑप्टिकल स्पष्टता, डिस्टोरशन मुक्त समतल सतह आदि के कारण इस उत्पाद के प्रयोग विभिन्न रूप से बढ़ते जा रहे हैं।
8. फ्लोट ग्लास को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लासवेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि संबद्ध वस्तु का आयात टैरिफ शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 और 7020 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में आने वाली संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। सब्सिडी प्राप्त आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत समान वस्तु मानी जानी चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद को 4 एमएम से 12 एमएम (दोनों शामिल हैं) के रेंज के नॉमिनल मोटाई के “क्लियर फ्लोट ग्लास” के रूप में परिभाषित किया गया है, नॉमिनल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है (इसके आगे “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है)।
11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में “ग्लास और ग्लासवेयर” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और सीमा शुल्क वर्गीकरण 7005 के अंतर्गत भी वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
12. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिक, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

14. प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है, अतः प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा जांच शुरुआत अधिसूचना के समान है।

घ. घरेलू उद्योग की दायर और उसकी स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. यह आवेदन मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स साइसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सेंट-गोबेन इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित हैं और उनके पास भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।
16. यह भी अनुरोध किया गया है कि उक्त उत्पादकों के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य उत्पादक गुजरात गार्डियन है। तथापि, उन्होंने संबद्ध देशों के विरुद्ध जांच का न समर्थन किया है और न विरोध किया है। अतः, नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर वे घरेलू उद्योग माने जाने के पात्र हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ.2 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में किसी उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. वर्तमान आवेदन मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, मैसर्स सेंट-गोबेन ग्लास इंडिया लिमिटेड और मैसर्स साइसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जिनका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में 82 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य ज्ञात उत्पादक मैसर्स गुजरात गार्डियन लिमिटेड है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त कंपनी ने जांच का समर्थन या विरोध नहीं किया है।
19. उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। आवेदकों ने यह भी बताया है कि वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग के मापदंडों और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित स्थिति को पूरा करते हैं। घरेलू उद्योग के आवेदन का वर्तमान जांच में देश में किसी अन्य उत्पादक ने कोई विरोध नहीं किया है।
20. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं/आवेदकों को नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग मानते हैं और आवेदन नियम 5 के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. प्रतिवादियों की गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. आवेदकों ने दावा किया है कि जहां तक उनके अनुरोधों/सूचना का संबंध है, गोपनीयता का दावा पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार किया गया है।
- ख. क्षति के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए आर्थिक मापदंडों को दिनांक 7.9.2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के अनुपालन में प्रदान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य मापदंडों का प्रकटन नहीं होने के कारणों को सिद्ध करना चाहिए।

- ग. भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते हैं। प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर का सार्थक सारांश प्रदान किए बिना पूर्णतः गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- घ. प्रतिवादी व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहे हैं।
- ड. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 7/2018 में बताए गए ढंग से आयात आंकड़े प्रस्तुत करने के दायित्व को पूरा नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस या प्राधिकारी से आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग की गोपनीयता के दावों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. आवेदकों ने सामान्य मूल्य की गणना, पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु निर्यात कीमत समायोजनों और प्रपत्र ए से एल में प्रदत्त सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आंकड़ों के रुझान प्रदान नहीं किए हैं जिनकी सूचना एक वर्ष से अधिक के लिए देनी चाहिए थी।
- ख. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। एकजोटिक डेकोन प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले के अनुसार, प्राधिकारी को आयात आंकड़े उसी ढंग और तरीके से उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें उन्हें दर्ज किया गया हो।
- ग. स्टरलाईट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2003 (158) ईएलटी 673 (एससी)] मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के समर्थक साक्ष्य के गोपनीय होने का दावा किया है, जिसे हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों हेतु प्रदान करना चाहिए था।
- ड. घरेलू उद्योग ने खरीद, बिक्री और मालसूची के संबंध में कंपनी की नीतियां नहीं बताई हैं।
- च. संबंधित निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर, प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार हैं और यदि प्राधिकारी को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे उसे प्रदान करेंगे।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत, सूचना की गोपनीयता के संबंध में यह प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच और तदनुसार समाधान किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय माना है।
25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी समस्त सूचना का अगोपनीय अंश प्रदान किया है जो वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत है।
26. सौदा-वार आयात सूची की एक्सल फाइल में अन्य हितबद्ध पक्षकारों को शेयर नहीं करने संबंधी अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 07/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा यथा-स्वीकृत आयातों को हार्ड कॉपी में लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से परिष्कृत आयात आंकड़े लेने के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार मांग सकते हैं। आवेदकों द्वारा यथा-स्वीकृत आयात आंकड़ों की स्कैन प्रति हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरुआत के साथ अंतिम निष्कर्ष के लिए अपेक्षाओं और मापदंडों की तुलना द्वारा पूरे मुद्दे को अस्पष्ट करने का प्रयास किया है चूंकि घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करते समय समस्त विहित प्रक्रिया को पूरा किया है, इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।
 - ii. निर्यातकों/बंगलादेश सरकार का यह अनुरोध कि निर्यात कीमत की गणना गलत और निराधार है, सही नहीं है क्योंकि उनके अनुरोध में विषय की मूल समझ का अभाव है। घरेलू उद्योग ने ऐसे खर्चों को घटाने के लिए माननीय प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि जो भू-पत्तन शिपमेंट पर भी लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री भाड़ा घटाया नहीं गया था क्योंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कटौती की राशि पर प्रश्न नहीं उठाया है, इसलिए घरेलू उद्योग ने उनके अनुरोध को अस्वीकृत करने का आग्रह किया है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या प्रमुख निविष्टियों अर्थात् गैस, सोडा एश की कीमतें अनुबंध-1 के अनुसार वास्तविक बाजार दशाओं को दर्शाती हैं अथवा नहीं।
 - iv. घरेलू उद्योग ने जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य की गणना के समय भारतीय निमावली का पालन किया है। इसके अलावा, जांच शुरू करते समय ट्रेड मैप के आंकड़ों से सामान्य मूल्य सूचना पर विचार करने से किसी लागू कानून या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार, जांच शुरुआत के लिए विचारित निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना भारतीय नगरपालिका कानूनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरी तरह पालन करती है। अतः, जांच शुरुआत के समय किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई पक्षपात नहीं हो सकता है।
 - v. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुएं किस रूप में भारत में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने यह जांच करने का अनुरोध भी किया है कि क्या बंगलादेश में बिक्रियां पर्याप्तता परीक्षण को पूरा करती हैं अथवा नहीं।
 - vi. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह अनुरोध नहीं किया है कि वे पाटन नहीं कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के दावे सही हैं। चूंकि जांच शुरुआत के समय घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़े उपलब्ध तथ्यों पर आधारित थे, इसलिए किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई पक्षपात नहीं हो सकता है क्योंकि अंतिम पाटन मार्जिन का परिकलन निर्यातकों द्वारा प्रदत्त संख्याओं पर आधारित होता है, बशर्ते कि उनके आंकड़े पूर्ण और सही हों।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- निर्यातक ने विहित प्रपत्रों के अनुसार अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, अगोपनीय अंश भी प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
 - घरेलू उद्योग संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं दे सका है और इसलिए अंतिम निर्धारण हेतु उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - प्राधिकारी को पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग अपने इस मामले को सिद्ध करने में विफल रहा है कि संबद्ध देशों में निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं।
 - बंगलादेश से निर्यात कीमत का अनुमान गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने समुद्री बीमा, पत्तन प्रभार, बैंक प्रभार, ऋण लागत आदि को घटाया है, जो मनमाना और गलत है क्योंकि अधिकांश आयात केवल भू-पत्तन से हुए हैं। प्राधिकारी को इस पहलू को भी देखना चाहिए।
 - घरेलू उद्योग ने अनुच्छेद 5.2 के मार्गदर्शन के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना की है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को सामान्य मूल्य से निर्यात कीमत पर विचार करना चाहिए था।
 - आवेदन में पाटन और क्षति मार्जिन के दावे काफी बड़ा-चढ़ाकर किए गए प्रतीत होते हैं और वह संगत और लागू तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत; बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।
30. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा बंगलादेश में संबद्ध वस्तु की प्रदत्त आयात कीमत एक निजी स्रोत (ट्रेड मैप) से ली गई है जो बंगलादेश में प्रचलित कीमतें दर्शाता है, यह अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 और नियम 5 का उल्लंघन है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ट्रेड मैप के आंकड़े संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग किए गए हैं। प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ बंगलादेश से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर भरोसा किया है और इसलिए इस तथ्य के कारण, किसी हितबद्ध पक्षकार से कोई पक्षपात नहीं हुआ है कि बंगलादेश में प्रचलित कीमतें संबद्ध जांच की शुरुआत के समय सामान्य मूल्य के रूप में ली गई हैं।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिसमें उनसे प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई थी। नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनएफजीआईएल") और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनजीआईएल") ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इन दोनों उत्पादकों के कारखाने और पंजीकृत कार्यालयों में मौके पर सत्यापन किया गया था और दोनों उत्पादकों को प्राधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन से संबंधित टिप्पणियां, यदि कोई हों, करने का निदेश देते हुए एक सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी। भागीदार उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की थी।
32. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध का विश्लेषण किया है और अंतिम जांच परिणाम में इस मुद्दे संबंधी प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों के साथ उनकी जांच की है।

क. बंगलादेश

क. नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनएफजीआईएल") और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनजीआईएल")

सामान्य मूल्य

33. नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनएफजीआईएल") और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनजीआईएल") बंगलादेश में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं और उन्होंने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्रियां की हैं। दोनों उत्पादकों ने अपेक्षित प्रपत्रों में संगत सूचना प्रदान की है।
34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बिक्रियां भारत में निर्यात की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण के लिए व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया था। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या लाभ वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं अथवा नहीं। यदि लाभ वाले सौदों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से अधिक है तो सभी घरेलू बिक्रियों को सामान्य मूल्य के निर्धारण में ध्यान में रखा जाता है और यदि लाभ वाले सौदे का प्रतिशत 80 प्रतिशत या उससे कम है तो केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जाता है। वर्तमान मामले में 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्रियां लाभप्रद हैं और इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।
35. एनएफजीआईएल और एनजीआईएल ने कमीशन और अंतरदेशीय परिवहन के लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। तथापि, ये दोनों कंपनियां दस्तावेजी साक्ष्य के साथ लक्ष्य कमीशन के लिए कटौती को सही सिद्ध करने में असमर्थ रही थीं और इसलिए इन्हें निर्यातक द्वारा दावों के समायोजन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।
36. तदनुसार, कारखानाद्वारा स्तर पर दोनों उत्पादकों अर्थात् नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएफजीआईएल) और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनजीआईएल) के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किए गए हैं और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए हैं।

निर्यात कीमत

37. एनएफजीआईएल और एनजीआईएल द्वारा प्रस्तुत उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनएफजीआईएल ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। एनजीआईएल ने भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। एनएफजीआईएल ने अपेक्षित प्रपत्र में संगत सूचना दी है।
38. पीओआई के दौरान, यह नोट किया गया है कि एनएफजीआईएल ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को एनएफजीआईएल *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। एनएफजीआईएल ने अंतरदेशीय परिवहन, पैकेजिंग लागत और पत्तन तथा अन्य संबंधित व्यय के लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। तदनुसार, इस समूह के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ख. बंगलादेश से अन्य उत्पादक

39. बंगलादेश के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विचार करते हुए, उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित करने का प्रस्ताव है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. थाइलैंड**थाइलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि थाइलैंड से उत्पादक/निर्यातक असहयोगी रहे हैं। थाइलैंड में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

पाटन मार्जिन**संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन**

41. यह नोट किया गया है कि संबद्ध जांच में नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएफजीआईएल) और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनजीआईएल) एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनी का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया रही है कि वह पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक ही कंपनी मानते हैं। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों की परिवर्चना प्रोत्साहित हो सकती है और इस प्रकार संबंधित निर्यातक उत्पादकों को न्यूनतम व्यक्तिगत पाटन मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत को उनके निर्यात भेजने में सक्षम बनाकर इन उपायों को निष्प्रभावी कर सकती है।
42. उपर्युक्त के अनुसार नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनएफजीआईएल) और नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनजीआईएल) दोनों के लिए भारत औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण उन्हें एकल कंपनी मानकर किया गया है और उन्हें एक ही पाटन मार्जिन प्रदान किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

43. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का नीचे दिए अनुसार निर्धारण किया गया है:

अमरीकी डालर/मी.ट.	उत्पादक	सामान्य मूल्य/सीएनएन (अमरीकी डालर/मी. ट.)	निर्यात मूल्य (अमरीकी डालर/मी. ट.)	पाटन मार्जिन (अमरीकी डालर/मी. ट.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
बंगलादेश	नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लि.	***	***	***	***	30-40
	नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लि.					
	अन्य	***	***	***	***	30-40
थाइलैंड	सभी उत्पादक	***	***	***	***	70-80

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न्यूनतम से कम सीमा से न केवल अधिक है अपितु पर्याप्त भी है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन**छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

45. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

- क. घरेलू उद्योग की लागत और विक्रय मूल्य की तुलना में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य काफी कम है। इससे काफी कम कीमत पर बिक्री एवं कीमत में कटौती हुई, इसके परिणामस्वरूप हानियां हुई। यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति एवं संबद्ध देशों से आयातों के बीच में संबंध को भी दर्शाता है।
- ख. संबद्ध देशों से आयात वर्ष 2017-18 में 64 मी.ट. थे जो पीओआई के दौरान बढ़कर 17362 मी.ट. हो गए हैं। 17298 मी. ट. की यह बढ़ोतरी काफी अधिक है। तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2018-19 के साथ तुलना करने पर भी संबद्ध देशों से आयातों में पीओआई में 6742 मी.ट. (63%) की बढ़ोतरी हुई। आयात मात्रा में यह पर्याप्त बढ़ोतरी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
- ग. वर्ष 2018-19 की तुलना में पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की कीमत में भी गिरावट हुई और वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग यही रही। यह घरेलू उद्योग पर दबाव और उनकी हानियों के कारणों को दर्शाती है।
- घ. पाटन मार्जिन लिखित आंकड़ों से काफी सकारात्मक हैं तथा सकारात्मक कम कीमत पर बेचना और कीमत में कटौती संबद्ध देशों से पाटित एवं हानिकर आयातों से शीघ्र सुरक्षा करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
- ङ. भारतीय बाजार में अपने-अपने बाजार हिस्से में बढ़ोतरी करने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातकों ने अपनी कीमतों में कमी की थी। यह तथ्य घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी प्रभाव को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करता है।
- च. बंगलादेश से आयातों ने घरेलू उद्योग के पूर्वोत्तर बाजार के बृहद हिस्से को ले लिया है। इसलिए, मात्रा की दृष्टि से घरेलू उद्योग की क्षति भी काफी है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उनकी बिक्रियों में क्षति जांच अवधि के दौरान बंगलादेश से आयातों में बढ़ोतरी होने की सीमा तक गिरावट आयी।
- छ. संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों की वजह से ही घरेलू उद्योग की अभी हानियां हो रही हैं। यह भी अनुरोध किया है कि कम कीमत के आयातों की वजह से ही घरेलू उद्योग अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपनी पूरी लागत को प्राप्त नहीं कर रहा है। संबद्ध देशों से कम कीमतों के आयात से घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी काफी दबाव बना है।
- ज. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा कीमत का अत्यधिक निर्धारण करने की वजह से बिक्री लागत और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को भरा नहीं जा सका। इसके परिणामस्वरूप हानियां हुई तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ हुआ है।
- झ. यह स्थिति घरेलू उद्योग पर कीमत संबंधी प्रभाव को साफ-साफ दर्शाती है जिसमें यदि वे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो उनकी नियत लागतों में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी तथा उनकी हानियों में भी बढ़ोतरी होगी।
- ञ. आवेदकों का व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपायों का आदतन प्रयोक्ता होने का जहां तक संबंध है, जब कभी एक स्रोत अथवा दूसरे स्रोत से शुल्क की सिफारिश की जाती है, तो पाटन की पुनः शुरुआत हुई है। निर्यातकों द्वारा आदतन पाटन के होते हुए घरेलू उद्योग को अनुचित व्यापार कार्य को रोकने के लिए प्राधिकारी से संपर्क करने से रोका नहीं जा सकता है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क व्यापार संबंधी अनुचित कदमों को रोकने के लिए होता है और न कि घरेलू उद्योग की सुरक्षा करने के लिए। अतः पाटन एवं उसकी परिणामी क्षति होने तक पाटनरोधी शुल्क लगाना औचित्यपूर्ण है।

- ट. अत्यधिक कीमत वाले बंगलादेश के निर्यातकों ने घरेलू उद्योग से पूर्वोत्तर बाजार से लिया है और घरेलू उद्योग उस बाजार के लिए प्रबंध करने में असमर्थ है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि बंगलादेश पूर्वी एवं पूर्वोत्तर बाजार को लक्षित कर रहा है तथा उसने पैराग्राफ अनुच्छेद 2.4.2 के दूसरे भाग के संदर्भ में बंगलादेश के निर्यातकों से पाटन को प्रकट करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है।
- ठ. थाइलैंड के निर्यातकों और बंगलादेश से अन्य उत्पादकों का असहयोग निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पाटन की स्वीकृति को साफ-साफ दर्शाता है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

46. घरेलू उद्योग को हुई क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- (i) संबद्ध देशों से हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति कोविड की वजह से ही हुई है और न कि संबद्ध देशों से हुए आयातों की वजह से हुई है।
 - (ii) घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असमर्थ रहा है कि उन्हें कीमत की वजह से या मात्रा की वजह से क्षति हो रही है। यह भी अनुरोध किया है कि मात्रा और कीमत संबंधी मापदंड क्षति जांच अवधि में सुधार को दर्शाते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अच्छा कार्य कर रहा है तथा संबद्ध देशों से हुए आयातों की वजह से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था।
 - (iii) यदि घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति केवल संबद्ध देशों से हुए आयातों का वजह से ही हुई थी या संबद्ध देशों से आयातों के अलावा अन्य कारणों की वजह से हुई थी, तो प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच करनी चाहिए।
 - (iv) आवेदकों द्वारा दिए गए आंकड़े 4 आवेदकों के समेकित आंकड़े हैं और इसलिए हितबद्ध पक्षकार व्यक्तिगत स्तर के आंकड़ों पर टिप्पणियां देने में असमर्थ हैं। अतः हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया कि प्रत्येक कंपनी के आंकड़े उनकी टिप्पणियों हेतु उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। समग्र तौर पर कुल आवेदकों के समेकित आंकड़ों पर कोई सार्थक टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
 - (v) चूंकि आयात संबंधी आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए कीमत संबंधी मानदंड के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
 - (vi) घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों से सुरक्षा के बारे में स्थायी तौर पर दावा किया है।
 - (vii) प्राधिकारी द्वारा संदर्भ कीमत आधारित शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक निर्यातकों को दंडित नहीं किया जाए।
 - (viii) घरेलू उद्योग पूर्वोत्तर बाजार में संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर रहा है और इसलिए प्राधिकारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर किसी प्रकार का पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित इसके नियम 11 में यह प्रावधान है कि “.....पाटित आयातों की मात्रा सहित सभी प्रासंगिक कारकों समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए” क्षति का निर्धारण करने में उन कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग की क्षति को निर्दिष्ट कर सकें।
48. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध II के पैरा (IV) में निम्नानुसार बताया गया है:
- “(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारक एवं सूचकांक; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले

कारक; पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, सामान-सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना शामिल होगा।”

49. डब्ल्यूटीए करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के अनुबंध II में (क) समान उत्पादों के लिए पाटित आयातों की मात्रा तथा घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों पर मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों में पर्याप्त बढ़ोतरी या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में हुई है। पाटित आयातों पर कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में काफी कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को अन्यथा कम करने के लिए है अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत संबंधी प्रभाव के बारे में तथा पाटन एवं क्षति के बीच क्षति एवं कारणात्मक संबंध होने की जांच करने के लिए कीमतों एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव के बारे में जांच की है।
50. क्षति और कारणात्मक संबंध संबंधी मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। आगे चलकर प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का स्वतः ही समाधान करता है।
51. नियमावली के अनुबंध II, पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि जहां पर एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के बारे में एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही हो, तो ऐसे मामले में प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव के बारे में सामूहिक रूप से मूल्यांकन करेंगे; यदि यह इस बात का निर्धारण करते हैं कि:
 - क) प्रत्येक देश से आयातों के बारे में सुनिश्चित पाटन मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक हो जो निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो तथा प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) हो, अथवा अलग-अलग देशों के निर्यात 3 प्रतिशत से कम हों, आयातों को संचयी तौर पर समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए लेखे में लिया जाता है; और
 - ख) आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना आयातित उत्पादों के बीच में प्रतिस्पर्धा की शर्तों तथा आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उचित होता है।
52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:
 - क) संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देशों से भारत में पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम से कम सीमा से अधिक हो।
 - ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक हो।
 - ग) आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित होता है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यातों की वजह उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई समान वस्तु के साथ न केवल प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धा होती है अपितु भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा होती है। यह नोट किया गया है कि जो उपभोक्ता घरेलू उद्योग से क्रय कर रहे हैं, वे भी संबद्ध देशों में से आयात कर रहे हैं।
53. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी, घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी तौर पर आकलन करने को उचित मानते हैं।
54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड विकृति को दर्शाएं। कुछ मापदंड विकृति को दिखा सकते हैं जबकि कुछ अन्य इसको न दिखाएं। प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी मापदंडों पर विचार किया है और उसके बाद में, यह निष्कर्ष निकाला है कि चाहे घरेलू उद्योग के लिए क्षति जारी रहती है अथवा इसकी पुनरावृत्ति होती है, ऐसे मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाता है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं तर्कों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुपरक जांच की है।

55. घरेलू उद्योग द्वारा पूर्वोत्तर बाजार के लिए संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है, हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा पूर्वोत्तर बाजार के लिए संबद्ध वस्तुओं की वास्तव में आपूर्ति की है।
56. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है तथा लिखित में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए इनका विश्लेषण किया है। उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का स्वतः ही समाधान हो जाता है।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू

I. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

57. पाटित आयातों पर मात्रा संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि क्या पाटित आयातों में पर्याप्त बढ़ोतरी या तो पूर्ण रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में हुई है। क्षति विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टमों से प्राप्त किए गए आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है क्योंकि डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों में सूचित की गई मात्रा से आयात की सही मात्रा प्रतिबिम्बित नहीं हो रही है। मांग का निर्धारण समस्त घरेलू उत्पादों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी देशों से आयातों के योग के रूप में किया गया है। संबद्ध वस्तुओं की स्पष्ट मांग/खपत क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
बंगलादेश से आयात	मी.ट.	0	0	668	7583
थाईलैंड से आयात	मी.ट.	64	1626	9952	9779
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	64	1626	10620	17362
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	248198	227326	197932	100692
कुल आयात	मी.ट.	248,263	228,952	208,552	118,054
घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	875,931	1,013,390	938,950	877,327
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	107	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री		190,000	230,000	145,000	140,000
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	76	74
घरेलू बिक्रियां- कुल		1,065,931	1,243,390	1,083,950	1,017,327
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	102	95
कुल मांग/खपत	मी.ट.	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	98	86

58. संबद्ध वस्तुओं की मांग में वर्ष 2018-19 तक बढ़ोतरी हुई और उसके बाद पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि तक गिरावट आयी। यह भी नोट किया गया है कि महामारी की वजह से पीओआई में मांग में गिरावट हुई। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि यह एक छोटी सी घटना थी जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। घरेलू उद्योग द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात मात्रा में बढ़ोतरी इस अल्प अवधि के दौरान बहुत ही पर्याप्त है तथा भारत में मांग की संभावना पर विचार करते हुए इन आयातों से घरेलू उद्योग की क्षति और बदतर हो सकती है।

II. आयात मात्रा और संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा:

59. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव एवं अन्य देशों से आयातों के बारे में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	मी.ट.	64	1626	10620	17362
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	248198	227326	197932	100692
कुल आयात	मी.ट.	248,263	228,952	208,552	118,054
विचाराधीन उत्पाद का कुल उत्पादन	मी.ट.	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग	मी.ट.	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
निम्नलिखित के बारे में संबद्ध देशों से आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2035	15116	27858
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2252	16758	31188

60. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, खपत और कुल आयातों के संबंध में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

61. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार प्राधिकारी को कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री करने, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करना होता है।

i. कीमत कटौती

62. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह विचार करना होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों को अन्यथा कम करने के लिए है अथवा कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए है जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। इस संबंध में संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, व्यापार के समान स्तर पर सभी छूट एवं करों के निवल के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का कारखानागत स्तर पर निर्धारण किया गया था।

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
बंगलादेश से आयात की मात्रा	मी.ट.	0	0	668	7583
बंगलादेश से पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	0	0	19376	19889
घरेलू निवल बिक्री वसूली	रु./मी.ट.	22,755	21,206	19,257	20,178
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	85	89
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	0	0	(120)	290
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	(1)	1
कीमत कटौती	%	0	0	(0.62)	1.46

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	(100)	236
कीमत कटौती	रेंज	0	0	Negative	0-10
थाईलैंड से आयात	मी.ट.	64	1626	9952	9779
थाईलैंड से पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	16178	19716	16412	16761
घरेलू निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी.ट.	22,755	21,206	19,257	20,178
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	85	89
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	6577	1490	2844	3418
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	23	43	52
कीमत कटौती	%	41	8	17	20
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	19	43	50
कीमत कटौती	रेंज	35-45	0-10	10-20	15-25
संबद्ध देशों से आयात	रु./मी.ट.	64	1626	10620	17362
संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य	रु./मी.ट.	16178	19716	16599	18127
घरेलू निवल बिक्री वसूली	रु./मी.ट.	22,755	21,206	19,257	20,178
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	85	89
कीमत कटौती	रु./मी.ट.	6577	1490	2658	2052
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	23	40	31
कीमत कटौती	%	41	8	16	11
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	19	39	28
कीमत कटौती	रेंज	35-45	0-10	10-20	10-20

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ii. कीमत हास/न्यूनीकरण

64. यह निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान कीमतों तथा पहुँच मूल्य में हुए परिवर्तन पर विचार किया कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतें पहले से कम हो रही हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी हद तक कीमतों का कम करना तथा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है जो अन्यथा बढ़ी हुई होगी।

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
विक्रय लागत	रु./मी.ट.	20,345	21,365	20,359	21,443
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	100	105
विक्रय मूल्य	रु./मी.ट.	22,755	21,206	19,257	20,178
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	85	89
संबद्ध देशों से आयातों का पहुँच मूल्य	रु./मी.ट.	16178	19716	16599	18127

65. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वर्ष 2019-20 तक गिरावट आई है और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है जबकि क्षति अवधि के दौरान पहुंच में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत से कम और संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से अधिक रही है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह बाजार में अपने सामान को बेचने के लिए आयात कीमत के अनुसार अपनी कीमतें रख रहा है और इस अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातों ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

66. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षा होती है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव की वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। पाटनरोधी नियमावली में यह प्रावधान है कि पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्रियों, लाभों, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव रखने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारक एवं सूचकांक; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, सामान-सूचियों, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए। तदनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों के बारे में इसमें नीचे विचार-विमर्श किया गया है।

i. क्षमता, उत्पादन बिक्री और क्षमता उपयोग

67. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
क्षमता	मी.ट.	1,499,264	1,995,360	2,055,910	1,885,810
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	137	126
उत्पादन- कुल	मी.ट.	1,296,914	1,705,946	1,622,524	1,325,883
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	125	102
उत्पादन- पीयूसी	मी.ट.	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	109	97
कुल उत्पादन के आधार पर क्षमता उपयोग	%	87	85	79	70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	91	81
घरेलू बिक्रियां	मी.ट.	875,931	1,013,390	938,950	877,327
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	107	100

68. घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष 2019-20 तक बढ़ोतरी हुई और उसके बाद, पीओआई के दौरान एक संयंत्र के बंद हो जाने के कारण पीओआई में इसमें गिरावट हुई। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2018-19 तक बढ़ोतरी हुई और उसके बाद उसमें गिरावट आयी, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग की वही प्रवृत्ति रही जो उत्पादन के मामले में थी। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि इसने अपनी स्तर पर उत्पादन करना जी रखा। संबद्ध देशों और अन्य देशों से कम कीमतें होने के बावजूद बने रहने के लिए कंपनी को इस प्रस्ताव की अनुमति दी गई। बिक्री की लागत विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को, जैसा कि दिखाया गया है, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा अधिक मूल्य-निर्धारण की वजह से समाप्त नहीं किया जा सका।

69. प्रबंधन द्वारा यथा सूचित एवं प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षमता के अनुसार घरेलू उद्योग ने क्षमता के लिए दावा किया है। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र में यथा सूचित क्षमता के बारे में प्राधिकारी ने विचार किया है। इसके अलावा, कोविड महामारी की वजह से पीओआई के दौरान भी कंपनी के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आयी।

ii. बाजार हिस्सा

70. कथित पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से के बारे में नीचे दिए अनुसार जांच की गई है:

बाजार हिस्सा	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
कुल मांग	मी.ट.	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	98	86
घरेलू बिक्रियां	%	81.11	84.45%	83.86%	89.60%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	103	110
संबद्ध देश	%	0.005	0.11	0.82	1.53
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2252	16758	31188
अन्य देश	%	18.89	15.44	15.31	8.87
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	81	47

71. यह नोट किया जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

iii. मालसूचियां

72. घरेलू उद्योग की मालसूचियों के बारे में नीचे दिए अनुसार जांच की गई है:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
औसत सामान-सूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	126	86

73. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर ने वर्ष 2019-20 तक वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, जांच की अवधि के दौरान मालसूची कम हो गई, क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण आयातित माल की आवाजाही प्रतिबंधित थी। तथापि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यह स्थिति अस्थायी है, क्योंकि स्थिति के सामान्य होने के बाद आयात में फिर से वृद्धि होगी।

iv. लाभ, निवेश पर लाभ तथा नकद लाभ

74. लाभ, नकद-लाभों तथा नियोजित पूंजी पर लाभ के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है:

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
बिक्रियां	मी.ट.	875,931	1,013,390	938,950	877,327
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	107	100
बिक्रियों की कीमत	रु. लाख	199,322	214,898	180,814	177,027
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	91	89
विक्रय मूल्य	रु./मी.ट.	22,755	21,206	19,257	20,178

विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	85	89
लागत	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	105	111
लागत	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	100	105
लाभ/हानि	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(8)	(30)	(99)
प्रति युनिट लाभ/हानि	रु./मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(7)	(46)	(53)
मूल्यहास	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	110	104
मूल्यहास	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	100	107
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	36	3
नकद लाभ	रु./ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	18	17
नियोजित पूंजी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	104	95
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(6)	(29)	(105)

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और आरओसीई में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की प्रति मी. टन लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ जांच की अवधि में नकारात्मक था।
76. घरेलू उद्योग ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से गैर-लाभकारी कीमतों के कारण घरेलू उद्योग को हानि हो रही है और संबद्ध देश से निरंतर कीमत दबाव में है, क्योंकि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री काफी सकारात्मक है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि शुल्कों की सिफारिश नहीं की जाती है तो घरेलू उद्योग की स्थिति और भी अधिक खराब होगी।
77. उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह अनिवार्य रूप से संबद्ध देशों से पाटित और हानिकारक आयातों के पाटित कीमतों पर आने के कारण है जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और इससे उन्हें क्षति हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की प्रति मीट्रिक टन लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ और ब्याज पूर्व लाभ भी प्रभावित हुए।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

78. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की प्राधिकारी ने नीचे दिए अनुसार, जांच की है:

वर्ष	युनिट	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई
उत्पादन	मी.ट.	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	109	97
कर्मचारी	संख्या	3,671	3,812	3,359	3,307
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	92	90
उत्पादन/कर्मचारी	मी.ट./सं.	277	331	330	298
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	119	107
मजदूरी	रु. लाख	12,057	14,153	15,211	12,397
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	126	103
मजदूरी/ कर्मचारी	रु./ सं.	328,450	371,284	452,845	374,869
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	138	114

79. तालिका से यह नोट किया जाता है कि:

- वर्ष 2019-20 तक उत्पादकता में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान गिरावट कोविड महामारी के कारण हो सकती है।
- घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है, उसके बाद पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और उन्हें भुगतान किया गया वेतन कम हो गया है।

vi. पाटन की मात्रा

80. पाटन की मात्रा उस सीमा का सूचक होती है जिस सीमा तक भारत में आयातों का पाटन किया जा रहा है और परिणामतः घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

vii. वृद्धि

81. उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग, लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नियोजित पूंजी पर लाभ, जैसे मापदंडों के काफी प्रतिकूल थे।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	पीओआई
उत्पादन	वाई/वाई	24%	-12%	-11%
क्षमता उपयोग	वाई/वाई	-2%	-6%	-9%
घरेलू बिक्रियां	वाई/वाई	16%	-7%	-7%
नकद लाभ	वाई/वाई	-46%	-45%	-13%
मालसूची	वाई/वाई	50%	-16%	-32%
निवेश पर लाभ	वाई/वाई	-7.43%	-2.88%	-0.41%

viii. नए निवेश जुटने की सामर्थ्य

82. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निगत में पाटित आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही है तथा अन्य उत्पादकों द्वारा देश में किए जा रहे पर्याप्त पूंजी निवेश पर विचार करते हुए पाटित आयातों के विरुद्ध सुरक्षा आवश्यक है।

पाटन मार्जिन की मात्रा/सस्ता बेचना

83. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गई उत्पादन लागत संबंधी सूचना/आंकड़ों को स्वीकार करके तथा पीओआई के लिए प्रैक्टिसिंग लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित करके निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना करने हेतु एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और यूटीलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार किया गया है। अनावर्ती व्यय को निकाल दिया गया है। नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत चल पूंजी सहित औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियों) पर उचित लाभ (22% की दर से पूर्व-कर) की कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। ताकि नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित और पालन की जा रही एनआईपी को प्राप्त किया जा सके।
84. पहुँच कीमत और उपर्युक्तानुसार निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

अमरीकी डालर/मी. ट.	उत्पादक/निर्यातक	एनआईपी (अमरीकी डालर/मी. ट.)	पहुँच मूल्य अमरीकी डालर/मी. ट.)	क्षति मार्जिन(अमरीकी डालर/मी. ट.)	क्षति मार्जिन %	रेंज
बंगलादेश	नामिर फ्लोट ग्लाम इंडस्ट्रीज लि.	***	***	***	***	10-20
	नामिर ग्लाम इंडस्ट्रीज लि.					
	अन्य	***	***	***	***	10-20
थाईलैंड	सभी उत्पादक	***	***	***	***	30-40

85. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के लिए सहयोगी उत्पादकों के साथ-साथ संबद्ध देशों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

86. प्राधिकारी ने नियमावली के सूचीबद्ध ऐसे अन्य कारकों को नोट किया है जिनसे घरेलू उद्योग के लिए पाटन और वस्तुगत क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ज.1. गैर-आरोपण विश्लेषण

87. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले अन्य ज्ञात कारकों के बारे में निम्नलिखित निर्णय देते हैं:

क. अन्य स्रोतों से आयात

88. संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात न्यूनतम से कम अथवा पाटित अथवा पाटन संबंधी उपायों के अध्यधीन हैं।

ख. मांग में कमी

89. भारत में विचाराधीन उत्पादों की मांग में कमी हुई है। तथापि, यह कोविड-19 के प्रभाव की वजह से हुई है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

90. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है।

घ. प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

91. व्यापार संबंधी ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं, जो प्राधिकारी की जानकारी में लायी गई हों और जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

92. संबंधित उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी में विकास को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारक नहीं माना जा सकता है।

च. निर्यात निष्पादन

93. यह नोट किया है कि प्राधिकारी द्वारा जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू कार्यों के बारे में ही है और इसलिए निर्यात मात्रा से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं बिक्री किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

94. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

95. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :

- क) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात में समग्र रूप से और साथ ही खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ख) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ग) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। संबद्ध सामानों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, कीमत कटौती के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।
- घ) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ आदि जैसे कीमत संबंधी आर्थिक मानदंडों की संख्या के संदर्भ में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो गई।
- ड) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुई मात्रा और कीमत प्रभावों ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान लाभ और आरओसीई नकारात्मक हो गए हैं।

96. इस प्रकार यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. प्रकटन पश्चात विवरण**अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध**

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. प्राधिकारी को डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों का खुलासा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीजी सिस्टम का खुलासा न करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा और इसलिए, मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- ख. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में निहित मोटाई के मुद्दों के कारण, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में और साथ ही अंतिम जांच परिणाम में डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास किया है, जैसा कि निर्यातकों द्वारा उल्लेख किया गया है।
- ग. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों की उचित रूप से जांच नहीं की है। इसके अतिरिक्त, अन्य कारकों की जांच भी उचित नहीं है।

- घ. संबद्ध देशों से आयातों की कम मात्रा के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी को थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ अन्य देशों से हुई क्षति का संचयन नहीं करना चाहिए। आगे यह भी अनुरोध किया गया था कि वर्तमान क्षति विश्लेषण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 का उल्लंघन है।
- ङ. प्राधिकारी को संदर्भ आधारित कीमत के आधार पर शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए।
- च. प्रकटन विवरण में आवेदकों द्वारा दिए गए बांग्लादेश से आयात की मात्रा को अस्वीकार करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिका में दिया गया साक्ष्य सटीक नहीं था और अनुच्छेद 5.3 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। यह अपने आप में जांच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार है।
- छ. विस्तृत क्षति विश्लेषण से पता चलता है कि बांग्लादेश से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- ज. प्राधिकारी ने स्वीकार किया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण मांग में संकुचन हुआ है और दूसरी ओर, प्राधिकारी ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग नहीं किया है।
- झ. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केवल 0.66% और 0.86% बाजार हिस्से के साथ आयात का स्रोत 77% बाजार हिस्से वाले घरेलू उद्योग के लिए शर्तें कैसे निर्धारित कर सकता है।
- ञ. प्राधिकारी ने हाल ही में मलेशिया के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया है। मलेशिया से आयात जांच की अवधि के 12 माह के 10 माह से अधिक समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे। इस प्रकार, यदि कोई क्षति होती है तो मलेशिया से आयातों के कारण इसकी अधिक संभावना है।
- ट. बांग्लादेश से सामग्री को वरीयता दी जाती है, क्योंकि वे भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी कीमत के हैं। प्राधिकारी को आयात कीमतों और घरेलू कीमतों की तुलना करते समय परिवहन लागत और ईंधन अधिभार को ध्यान में रखना चाहिए और व्यापार के समान स्तर पर कीमतों की तुलना करने के लिए उपयुक्त समायोजन करना चाहिए तथा तदनुसार अंतिम जांच परिणाम जारी करना चाहिए।
- ठ. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में प्रकटन विवरण में प्रकट किए गए अपने मार्जिन के साथ-साथ निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पहुँच कीमत की पुष्टि करनी चाहिए।
- ड. आवेदक ने पाटन का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है और इसलिए मामले को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ढ. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता की जांच करनी चाहिए।

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध:

98. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- क. प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम में पाटन मार्जिन की पुष्टि करनी चाहिए और भाड़ा पर विचार करके क्षति मार्जिन को समायोजित करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी आयात केवल पूर्वोत्तर बाजार में केंद्रित हैं। अतः, पूर्ण क्षति संरक्षण के लिए, इस मामले में क्षति मार्जिन परिकलन में भाड़ा समायोजन आवश्यक है।
- ख. प्राधिकारी कृपया जांच की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए बांग्लादेश के आयातों के क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू बिक्री के लिए भाड़ा लागत को समायोजित करें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह दृष्टिकोण विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 2 में निर्धारित निष्पक्ष तुलना के सिद्धांत के अनुरूप होगा।
- ग. प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से सकारात्मक पाटन हो रहा है जिससे घरेलू उद्योग को काफी वास्तविक क्षति हो रही है और इसीलिए प्राधिकारी को यथाशीघ्र पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए।
- घ. संबद्ध देशों से आयातों के कम हिस्से की कोई संगतता नहीं है, क्योंकि संगत मानदंड यह है कि आयात, भारत में कुल आयात का न्यूनतम 3% होना चाहिए। स्थापित न्याय व्यवस्था के अनुसार, मांग में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से की कोई संगतता नहीं है।

- ड. प्राधिकारी को वर्तमान क्षति के अलावा आगे की क्षति के खतरे का भी विश्लेषण करना चाहिए ताकि संबद्ध आयातों द्वारा की गई वास्तविक और संभावित क्षति की पूरी तस्वीर प्राप्त हो सके, क्योंकि जांच की अवधि के बाद के आयातों में काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2022 के पहले चार माह में बांग्लादेश से लगभग 14372 मीट्रिक टन आयात देखा है, जो काफी है।
- च. चूंकि बांग्लादेश में उत्पादकों के पास पर्याप्त स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल क्षमता है और वे इसे और बढ़ा रहे हैं, अतः यह क्षति के स्पष्ट एवं आसन्न खतरे और संबद्ध देशों से पाटित और क्षतिकारक आयातों के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता और महत्व को दर्शाता है।
- छ. मैसर्स नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक चीनी कंपनी 'ट्रायम्फ इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कं. लिमिटेड (सीटीआईईसी)' के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों अतिरिक्त लाइनें प्रति दिन 600 मीट्रिक टन संबद्ध सामान का उत्पादन करने में सक्षम हैं, जिससे प्रति वर्ष 4,38,000 मीट्रिक टन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारत, पड़ोसी देश होने के नाते और बाजार में बहुत अधिक कीमत वसूली होने के कारण, बांग्लादेश में निर्यातकों के लिए संबद्ध सामानों को पाटित करने के लिए पहली पसंद का लक्ष्य होना तय है। इसके अतिरिक्त, जिनई ग्लास होल्डिंग्स लिमिटेड, चीन, जो चीन में सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास विनिर्माता है, ने बांग्लादेश में 200 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करके एक फ्लोट ग्लास फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए कुछ अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति के हैं। इन अनुरोधों की अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर पहले ही जांच की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है:
- क. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का संबंध है कि प्राधिकारी आयात आंकड़ों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन पत्र की वैधता का उचित रूप से मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए आंकड़े केवल जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से पर्याप्त थे। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने जांच शुरू करने और अंतिम जांच परिणाम के समय प्राधिकारी के दायित्व को गलत समझा है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने नियम 5 के अनुसार याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर जांच शुरू करने के लिए सही कदम उठाया है। यह भी एक सिद्ध कानून है कि प्राधिकारी द्वारा उचित जांच और सत्यापन के बाद घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अंतिम निर्धारण के लिए आधार होना अपेक्षित है। अतः, यह स्पष्ट है कि जांच शुरू करने और अंतिम जांच परिणाम के समय जांच प्राधिकारी के दायित्व अलग-अलग हैं। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि जांच प्रक्रिया के दौरान अर्थात् जांच शुरू करने के बाद, प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों से उत्तर प्राप्त होते हैं, और घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन भी करते हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी निर्यातकों, घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्यापित आंकड़ों के अनुसार चलते हैं और इस प्रकार, जांच के दौरान सत्यापन के आधार पर शुरू में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में सुधार, सुधार/संशोधन किया जाता है। चूंकि वर्तमान जांच परिणाम विधिवत सत्यापित सूचना पर आधारित हैं, अतः किसी भी हितबद्ध पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता।
- ख. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के उल्लंघन से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश (बांग्लादेश और थाईलैंड) से आयात के संबंध में सिद्ध पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है, जैसा कि अनुच्छेद 5 के पैरा 8 में परिभाषित है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा नगण्य नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता/आयातक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों के साथ-साथ आयातों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि सभी निर्धारित मानदंड पूरे हैं, अतः प्रकटन विवरण में प्रस्तावित और अंतिम जांच परिणामों में किया गया संचयी विश्लेषण सही है और पूरी तरह से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 के अनुरूप है।

- ग. प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों और उनके प्रकटन के स्थान पर डीजी सिस्टम के आंकड़ों का प्रयोग किए जाने के बारे में तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने चर्चा के दौरान अनुरोध किया कि उन्होंने एक विशेष बीजक के तहत विभिन्न मोटाई के फ्लोट ग्लास का निर्यात किया है। तथापि, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में उस बीजक की पूरी मात्रा को केवल एक मोटाई शीर्ष के तहत सूचित किया गया है। निर्यातकों द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुसार, इससे भारत को उनके निर्यातों की सीआईएफ कीमतें प्रभावित हुई हैं। डीजी सिस्टम के आंकड़ों और निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर के विश्लेषण के बाद, निर्यातकों के अनुरोध में विश्वसनीयता पाई गई। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में समग्र आंकड़ों के सार का पूरी तरह से प्रकट किया है और इसीलिए, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त के अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि लेन-देन की उचित जांच और आवश्यक विश्लेषण के बाद ही, डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर, जहां तक संभव हो, निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यात मात्रा का सहसंबंध बनाने और दायर उत्तरों को वैध करने के लिए आयात मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए विश्वास किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कारणात्मक संपर्क से संबंधित मुद्दों को प्रकटन विवरण के संगत भाग में और इन अंतिम जांच परिणामों में भी विस्तार से हल किया गया है। चूंकि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के विश्लेषण के विपरीत कोई नया अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसीलिए प्राधिकारी अपने क्षति विश्लेषण की पुष्टि करते हैं।
- ङ. प्राधिकारी ने नोट किया है कि मलेशिया से पाटित आयातों से भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है, तथापि, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष इस तथ्य को नहीं रोकता है कि बांग्लादेश और थाईलैंड से आयातों के कारण साथ-साथ क्षति हो रही है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष जांच में संबद्ध देशों से आयात क्षति का एकमात्र अथवा प्रमुख कारण हो। प्राधिकारी के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों से जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह तर्क कि मलेशियाई आयातों से भी क्षति हुई है, का इस मामले में कोई परिणाम का आधार नहीं है।
- च. बांग्लादेश से प्रतिभागी निर्यातकों के साथ-साथ आयातकों/प्रयोक्ताओं और उनके एसोसिएशनों से संदर्भ-कीमत आधारित शुल्क के अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने विश्लेषण उपलब्ध कराई गई सूचना और मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर उनके अनुरोध का विश्लेषण किया है तथा मामले के वास्तविक मैट्रिक्स का विश्लेषण करने के बाद संदर्भ कीमत-आधारित शुल्क की सिफारिश की है।
- छ. वास्तविक क्षति के खतरे के विश्लेषण के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में, चूंकि जांच की शुरुआत के बाद आयातों में कई गुना वृद्धि हुई है, अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति दर्शाती है।
- ज. क्षति मार्जिन के परिकलन में भाड़े के समायोजन के बारे में प्रयोक्ता/आयातक के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किए जाने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि क्षति मार्जिन का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-III के संदर्भ में प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार किया गया है।
- झ. कोविड-19 के प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करने से संबंधित अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि सामान्यीकरण और अनुकूलन के सिद्धांतों को अपनाकर क्षतिरहित कीमत के परिकलन में कोविड के प्रभाव को पर्याप्त रूप से हल किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद की अंतर्निहित प्रकृति के कारण, घरेलू उद्योग के पास जांच की पूरी अवधि के दौरान अपनी भट्टी और उत्पादन को चालू रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने अनुरोध को सिद्ध करने के लिए कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया है कि कैसे कोविड ने घरेलू उद्योग के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ञ. संबद्ध देशों से आयातों की कम मात्रा संबंधी अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात कुल आयातों के 3% से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया जाता है कि आयातों की कम मात्रा के बावजूद, घरेलू उद्योग उनकी कीमत से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, और वह अपनी कीमतों को गैर-

लाभकारी स्तरों पर रखने के लिए मजबूर हो जाता है, जो अंततः उनके प्रचालन निष्पादन को प्रभावित कर रहा है।

- ट. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित अपर्याप्त सूचना से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई थी। यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में सत्यापित सूचना का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश और थाईलैंड के अन्य गैर-प्रतिभागी निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सूचना का उपयोग किया है और इसीलिए, किसी भी हितबद्ध पक्षकार के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है।

घ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

100. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन की परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जा सकेगा, घरेलू उत्पादकों की गिरावट को रोका जा सकेगा जो उन अधिकतर छोटे और सूक्ष्म लघु क्षेत्र के हैं, और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
101. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी उपाय लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने जांच की कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क लगाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों संबंधी सूचना पर विचार करने पर आधारित है।
102. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल था। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, घरेलू उद्योग की स्रोतों में जाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उन कारकों के संबंध में सूचना मांगी जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी आने अथवा देरी होने की संभावना है। कुछ आयातकों और एक एसोसिएशन ने जांच में भाग लिया। यह नोट किया जाता है कि न तो आयातक और न ही एसोसिएशन ने पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के संबंध में कोई संगत सूचना दी है। इसके विपरीत, उन्होंने स्वीकार किया है कि केवल कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण वे संबद्ध देशों से खरीद कर रहे हैं। उन्होंने संदर्भ-कीमत तंत्र पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का भी अनुरोध किया है, ताकि सभी संबंधितों के हितों की रक्षा की जा सके।
103. इसके अतिरिक्त, इस संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे, और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
104. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव निर्धारित करने के लिए प्रारूप निर्धारित किए हैं और विस्तार से बताया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तथापि यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जांच का समर्थन करने वाले विभिन्न सूक्ष्म स्तर के संगठनों से जांच की शुरुआत के बाद के पत्र स्पष्ट रूप से उनके लिए जांच की महत्ता दर्शाते हैं। अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क

का प्रभाव बहुत ही कम होगा लेकिन यह उनके वसूली पथ में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क न लगाने से संबंधित उत्पाद के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है और प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित में होगा। इसके मद्देनजर, संदर्भ कीमत-आधारित शुल्कों की सिफारिश करने से घरेलू उद्योग के साथ-साथ निर्यातकों सहित हितबद्ध पक्षकारों के वाणिज्यिक और कानूनी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट. निष्कर्ष और सिफारिशें

105. इन जांच परिणामों में दर्ज किए गए तर्कों, प्राप्त सूचनाओं, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा यहां ऊपर की गई घरेलू उद्योग को हुई पाटन एवं परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।
- ख. संबद्ध सामानों के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में खपत के संबंध में भी वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। संबद्ध सामान की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, कीमत कटौती से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है।
- घ. यह कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुई मात्रा और कीमत प्रभाव से जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और आरओसीई नकारात्मक हो गए हैं।
- ङ. इन संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।
- च. हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनीय सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। चूंकि सिफारिश किए गए शुल्क कमतर शुल्क नियम पर आधारित हैं, अतः सिफारिश किए गए शुल्क काफी उचित हैं और इससे निचले स्तर के उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
- छ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलुओं के संबंध में सूचना देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
- ज. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। इस मामले के वास्तविक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए और दी गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण/संदर्भ प्रपत्र की सिफारिश करना पयुक्त माना जाता है। प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए संबद्ध सामानों के पहुँच मूल्य और संदर्भ कीमत के बीच के अंतर के रूप में, बशर्ते कि पहुँच मूल्य कॉलम 7 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

झ. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 88, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों के लागू स्तर के रूप में निर्धारणीय होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	उप-शीर्ष बयवा टैरिफ मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	संदर्भ कीमत	मापन की यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7005	साधारण मोटार्ड बीआईएस 14900: 2000 के अनुसार होने पर 4 मिमी से 12 मिमी (दोनों मिलाकर) तक की साधारण मोटार्ड के क्लीयर फ्लोट ग्लास	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	नासिर फ्लोट ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.
2.	-वही-	-वही-	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	नासिर ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.
3.	-वही-	-वही-	बांग्लादेश	बांग्लादेश सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.
4.	-वही-	-वही-	बांग्लादेश और थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	बांग्लादेश	कोई अन्य	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.
5.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	कोई अन्य	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.
6.	-वही-	-वही-	बांग्लादेश और थाईलैंड को छोड़कर कोई भी देश	थाईलैंड	कोई अन्य	306.10	मी. टन	अमे. डॉ.

क. आगे की प्रक्रिया

106. केंद्र सरकार द्वारा ये जांच परिणाम स्वीकार किए जाने के बाद इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 29th June, 2022

Case No. AD (OI) 10/2021**Subject : Anti-Dumping investigation concerning imports of Clear Float Glass from Bangladesh and Thailand.**

No. 6/10/2021-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof.

A. Background

1. M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s Sisecam Flat Glass India Private Limited and M/s Saint-Gobain India (Pvt.) Limited (hereinafter also referred to as “domestic industry” or “applicants” or “petitioners”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules) imposition of Anti-dumping duty on imports of Clear Float Glass (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration”), originating in or exported from Bangladesh and Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. Whereas the Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicants on behalf of the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/10/2021 -DGTR dated 30.06.2021, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. Procedure

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a) The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants on behalf of the domestic industry, alleging dumping of ‘Clear Float Glass’ from Bangladesh and Thailand.
 - b) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of an anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - c) The Authority issued a public notice dated 30.06.2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
 - d) The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e) The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.

- f) The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- g) The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- (i) PHP Float Glass Industries, Bangladesh
 - (ii) Usmania Glass Sheet Factory Ltd., Bangladesh
 - (iii) Nasir Float Glass Industries Ltd., Bangladesh
 - (iv) Kabinburi Glass Industry. Thailand
 - (v) AGC Asia Pacific Pte. Ltd., Thailand
- h) The exporter's questionnaire has been filed by only Nasir Float Glass Industries Limited (NFGIL), and Nasir Glass Industries Limited (NGIL) from Bangladesh. No other producer / exporter has filed the exporters questionnaire response.
- i) The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Atlantic Trading – Mumbai
 - b. Kanch Ghar – Mumbai
 - c. Fishfa Glass – Mumbai
 - d. Samarth Industries – Mumbai
 - e. Prashanth Trading – Mumbai
 - f. Asmi Traders – Mumbai
 - g. Rajat Glass Traders – Karad
 - h. Chandan Glass Traders – Pune
 - i. Kochhar Glass Traders – Bhopal
 - j. Ganeriwala Brothers Pvt Ltd – Kolkata
 - k. Sure Safe Group/ Ganeriwala Glass Traders- Kolkata
 - l. M S Glass Traders- Kolkata
 - m. Glaze Architecture Pvt Ltd. - Kolkata
 - n. Glaze Infrastructure P Ltd.- Kolkata
 - o. Saraf Glass P Ltd. - Kolkata
 - p. GSC - Noida
 - q. Shiv Shakti - Roorkee
 - r. Ridhi Sidhi - Jaipur
 - s. Banaras Glass - Lucknow
 - t. T. L. Verma - Chandigarh
 - u. Jagdamba Glass - Delhi
 - v. Sheesh Mahal Tuff - Rohtak
 - w. Nutan Glass Hs(P) Ltd. - Bangalore
 - x. Mahaveer Glass Hs - Bangalore
 - y. Karnataka Metal Company - Bangalore

- z. Impact Safety Glass (P) Ltd - Bangalore
 - aa. Southern Auto Products (P) Ltd. - Bangalore
 - bb. Tough Glass India- Bangalore
 - cc. Yesho Float Glass (P) Ltd. - Hyderabad
 - dd. Bhandari Glass Co. - Hyderabad
 - ee. Prakash Glass - Hyderabad
 - ff. Mahaveer Glass - Chennai
 - gg. Mahaveer Mirror - Vishakhapatnam
 - hh. Uma Industries – Bangalore
 - (ii) Jai Mirror Industries – Chennai
- j) The following importers and user association have filed their questionnaire responses:
- (i) M/s Ayur Marketing Pvt. Ltd.
 - (ii) M/s K. K. Enterprise
 - (iii) M/s Asha
 - (iv) Federation of Safety Glass (FOSG)
- k) The period of investigation (POI) for the present investigation 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 months). The injury period under investigation, however, covers the periods April 2017 to March 2018, April 2018 to March-2019, April 2019 to March 2020, and the POI
- l) The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented/submissions made by the various interested parties through email.
- m) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and DG-Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. During the discussions, it was noted that the exporters have exported float glass of various thicknesses under a particular invoice. However, the DGCI&S data has reported the entire such quantity of that invoice under only one thickness head. This has impacted the CIF prices of their exports to India. After analysis of DG Systems data and exporters' questionnaire response, credence was found in the request of the exporters. In view thereof, after due examination of the transactions and required analysis, DG Systems data has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
- n) A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- o) In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 22.11.2021 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- p) Further information was sought from the applicants to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- q) The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to

the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- r) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the domestic industry and the cooperating exporter was carried out to the extent necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of this final finding.
- s) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
- t) The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final finding, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.
- u) The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v) A disclosure statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 09.06.2022 and the interested parties were allowed time up to 15.06.2022 to comment on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.
- w) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final finding on the basis of the facts available.
- x) *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹75.02

C. Product under Consideration and Like Article

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

The product under consideration in the present investigation is defined as "Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)", the nominal thickness being as per BIS 14900:2000, originating in or exported from Bangladesh and Thailand.

Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror, solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.

Float Glass is classified under Chapter Heading 70 "Glass and glassware". However, the subject goods are also being imported under tariff sub-headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C.1 Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

5. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article.

C.2 Submissions made by the domestic industry

6. The product under consideration (PUC) for the purpose of the present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000.
7. Clear Float Glass is used in construction, refrigeration, mirror and solar energy industries etc. The product is a superior quality of glass. Due to its inherent strength, high optical clarity, distortion free smooth surface etc., the applications of the product have been increasing for different purposes.
8. Float Glass is classified under Chapter Heading 70 “Glass and glassware”. However, the subject goods are also being imported under tariff headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019 and 7020. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way binding upon the product scope of the Customs Tariff Act, 1975.
9. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market & tariff classification of the goods. The applicants have claimed that the subject goods, which are coming into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidized imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules.

C.3 Examination by the Authority

10. The product under consideration in the present investigation was defined as “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness being as per BIS14900:2000 (hereinafter referred to as the “subject goods”).
11. The product under consideration is classified under the category “Glass and Glassware” in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
12. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-dumping Rules provides as under:
“like article” means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.”
13. The Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the Indian industry and exported from the subject countries. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of anti-dumping Rules.
14. No other argument has come across to the Authority regarding the product under consideration and like article issue. The Authority, therefore, confirms that the scope of the product under consideration as that of the initiation notification.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**D.1 Submissions made by the domestic industry**

15. The application has been filed by M/s Asahi India Glass Limited, M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s Sisecam Flat Glass India Private Limited and M/s Saint-Gobain India (Pvt.) Limited. The applicants have also certified that they have neither imported the subject goods from subject countries nor they are related to any exporter or importer of the subject goods and account for major proportion of the total production of the subject goods in India.

16. It is also submitted that apart from the above-producers, there is only one other producer of the subject goods in India, namely Gujarat Guardian. However, they have neither supported nor opposed the investigation against the subject countries. Therefore, they are eligible to be considered as the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(b) of the Rules supra.

D.2 Submissions made by the interested parties

17. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to the scope and the standing of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

18. The current application has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Ltd., M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Saint-Gobain Glass India Ltd. and M/s Sisecam Flat Glass India Ltd., who collectively command 82% share in Indian production of the subject goods during the period of investigation. As per the information available with the Authority there is only one other known producer of the product under consideration in the country i.e., M/s Gujarat Guardian Ltd. It is also noted that the said company has neither supported nor opposed the investigation.
19. As per the available information, none of the applicants, has imported the subject goods from the subject countries. It was further submitted by the applicants that they are not related to any importer or exporters of the subject goods. In view of the above, the Authority considers that the applicants fulfil the criteria of domestic industry and the standing as laid down under the Indian Anti-dumping Rules. There is no opposition to the domestic industry's application from any other producer in the country in the present investigation.
20. In view of the above, the Authority holds the petitioners/applicants as domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the domestic industry

21. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality claims of the respondents:
- The applicants have claimed that as far as their submissions / information are concerned, confidentiality has been claimed in accordance with the provisions of Rule 7 of the Anti-dumping Rules and the Trade Notices issued in this regard.
 - The economic parameters considered by the Authority for the purpose of arriving at the determination of injury have been provided in compliance with trade notice 10/2018 dated 7.09.2018. Interested parties should establish prejudice caused on non-disclosure of other parameters.
 - The response filed by the participating producers fail to comply with the requirements laid down by the Authority with regard to confidentiality. Response to most of the questions in questionnaire have been claimed completely confidential with no meaningful summary provided.
 - The respondents have failed to comply with the requirements of the Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018.
 - The domestic industry has fulfilled the obligation of providing the import data in the manner stated in the Trade Notice 07/2018. The interested parties are free to obtain data from DGCI&S or from the Authority.

E.2 Submissions made by the other interested parties

22. The producers/exporters/other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality claims of the domestic industry
- The applicants have claimed excessive confidentiality with respect to normal value computation, export price adjustments for determining dumping margin and information provided in Format A to L. Moreover, the domestic industry has not provided trend of data wherein information was to be given for more than one year.

- b. The domestic industry has not made available DGCI&S data. As per Exotic Décor Pvt. Ltd. and Ors. v. Designated Authority, the Authority has to make available import data in same form and manner in which it was taken on record.
- c. Reliance is placed on the decision of Supreme Court in the case of Sterlite Industries (India) Ltd. Versus Designated Authority [2003 (158) ELT 673 (SC)].
- d. The domestic industry has claimed supporting evidence for normal value, export price as confidential, which ought to be provided for comments from the interested parties.
- e. The domestic industry has not provided company policies on purchase, sales and inventory.
- f. Responses filed by the respective exporters are as per the Authority's consistent practice and in case, the Authority requires any clarification, they will provide the same.

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”
24. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. All the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
25. The Authority notes that the domestic industry and the other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of the present investigation.
26. On the submission by the other interested parties on excel file of transaction wise import listing not shared, the Authority notes that Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018 provides that the sorted imports as relied by the domestic industry can be obtained in hard copy. Additionally, interested parties can seek authorization from the Authority to seek raw import data from DGCI&S. The scanned version of the import data as relied on by the applicants was made available to the interested parties.

F. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1 Submissions by the domestic industry

27. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
 - i. The interested parties have tried to obfuscate the whole issue by comparing the requirement and yardsticks for final conclusion with initiation. Since domestic industry has completed all the prescribed procedures while filing the application, the submissions of the interested parties need to be rejected.

- ii. The submission of the exporters / government of Bangladesh that computation of export price is wrong, and baseless is incorrect, as their submissions lacks basic understanding of the subject. The domestic industry has requested the Hon'ble Authority to deduct only those expenses which are applicable for land port shipments also. For example, Ocean freight was not deducted. Since none of the interested parties has questioned the quantum of deduction, the domestic industry requested to reject their submissions.
- iii. The domestic industry has requested the Authority to check whether the prices of the major inputs namely gas, soda ash are reflective of true market conditions or not in terms of Annexure I.
- iv. The domestic industry has followed the Indian Rules while computing the normal value for the purpose of the initiation. Further, while initiating the investigation, considering normal value information from Trade Map data has not violated any applicable laws and international obligation. Thus, the information relating to export price and normal value considered for initiation fully met with the Indian municipal laws as well as the international obligations. Therefore, there can be no prejudice to any interested party can cause at the time of initiation.
- v. The domestic industry requested the Authority to check in which form subject goods are entering India. They have also requested to check whether sales in Bangladesh meets sufficiency test or not.
- vi. None of the interested parties has submitted that they are not dumping. This shows that the claims of the domestic industry are correct. Since estimations provided by the domestic industry at the time of initiation based on facts available, no prejudice can be caused to any interested parties, as final dumping margin would be computed based on the numbers provided by the exporters, provided their data is complete and accurate.

F.2 Submissions of the other interested parties

28. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. Exporter has filed its response as per prescribed formats. Further, non-confidential version is also submitted as per consistent practice of the Authority.
 - ii. The domestic industry has failed to provide any reliable information in relation to normal value and export price of the subject goods in the subject countries and therefore, the same should not be considered for final determination.
 - iii. The Authority should consider the information filed by the producer / exporter for determining dumping margin.
 - iv. The domestic industry failed to establish its case that exporters in the subject countries are dumping the subject goods in India.
 - v. Estimation of export price from Bangladesh is incorrect, as the domestic industry deducted marine insurance, port charges, bank charges, credit cost, etc., are arbitrary and incorrect, as most of the imports is from land port only. The Authority should look into this aspect also.
 - vi. The domestic industry has not computed the normal value as per guidance of Article 5.2. Moreover, the domestic industry ought to have considered the export price from the normal value.
 - vii. The claims of dumping and injury margin in the application appear highly exaggerated and are not based on relevant and applicable facts.

F.3 Examination by the Authority

29. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance both the rules made under sub-section (6); or*

- ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
- comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a countries other than the countries of origin and where the article has been merely transhipped through the countries of export or such article is not produced in the countries of export or there is no comparable price in the countries of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the countries of origin.

30. As regard the submissions of the interested parties that the import prices of the subject goods into Bangladesh provided by the domestic industry from a private source (Trade Map) as an indicator of the prevailing prices into Bangladesh, is violation of Article 5, Article 2 and Rule 5, the Authority notes that the Trade Map data has been used only for the purpose of initiation of the subject investigation. The Authority has relied on the data provided by the producers/exporter of the subject goods from Bangladesh for the purpose of this final finding , and hence, there is no prejudice to any interested party on account of the fact that the prevailing prices in Bangladesh were taken as normal value at the time of initiation of the subject investigation.
31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Nasir Float Glass Industries Limited (“NFGIL”) and Nasir Glass Industries Limited (“NGIL”) have filed the exporter's questionnaire response. An onsite verification was conducted at the factory and registered offices of both the producers, and a verification report was issued to both the producers asking them to provide comments, if any, pertaining to the verification conducted by the Authority. No comments were filed by the participating producers and exporters.
32. The Authority has analyzed the submissions made by the interested parties including the domestic industry and examined the same along with the comments received on disclosure statement on this issue in the final findings.

A. Bangladesh

a. Nasir Float Glass Industries Limited (“NFGIL”) and Nasir Glass Industries Limited (“NGIL”)

Normal Value

33. Nasir Float Glass Industries Limited (“NFGIL”) and Nasir Glass Industries Limited (“NGIL”) are related producers of the subject goods in Bangladesh and have made sales of the subject goods in the domestic market during the period of investigation. Both the producers have provided relevant information in the requisite formats.
34. The Authority notes that domestic sales are in sufficient volume when compared with exports to India. The Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of sales of the subject goods. The Authority examined whether the profit-making transactions are more than 80% or not. If the percentage of profit-making transactions is more than 80%, then all the transactions in the domestic market are considered for determination of normal value and if the percentage of profit making transactions is 80% or less, only the profitable domestic sales are taken into consideration for determination of normal value. In the present case, more than 80% of the domestic sales are profitable and hence all the domestic sales have been considered to determine the normal value.
35. NFGIL and NGIL have claimed adjustments for commissions and inland transportation and same have been allowed by the Authority. However, both the companies were not able to substantiate the

deduction for target commission with documentary evidence, and hence the same was not accepted as adjustments claimed by the exporter.

36. Accordingly, weighted average normal values for both producers i.e. Nasir Float Glass Industries Limited (NFGIL), and Nasir Glass Industries Limited (NGIL) at ex-factory level has been determined and the same is shown dumping margin table below.

Export price

37. From the response filed by NFGIL and NGIL, the Authority has noted that NFGIL has produced and exported the subject goods directly to unrelated customers in India. NGIL has not exported the subject goods to India. NFGIL has provided the relevant information in requisite formats.
38. During the POI, it is noted that NFGIL has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. NFGIL has claimed adjustments on account of inland transportation, packaging cost and port & other related expenses and the same has been allowed by the Authority. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for the group has been determined and shown in the dumping margin table below.

b.Other producers from Bangladesh

39. The normal values and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Bangladesh is proposed to be determined as per facts available considering the data provided by cooperating producer and is same is mentioned in the dumping margin table below.

B. Thailand

Normal value and Export price for all producers/exporters from Thailand

40. The Authority notes that no exporter/producer from Thailand has responded to the Authority in the present investigation. Therefore, the Authority considers that the producers/exporters from Thailand have preferred non-cooperation. For all the non-cooperative exporters/producers in Thailand, the Authority has determined the normal value and export price on the basis of facts available. The normal value and export price so determined is given in the dumping margin table below.

DUMPING MARGIN

Dumping margin for related producers and Exporters

41. It is noted that in the subject investigation M/s Nasir Float Glass Industries Limited (NFGIL), and M/s Nasir Glass Industries Limited (NGIL) are related to each other and form a group of related company. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

42. In accordance with the above, one weighted average normal value for both M/s Nasir Float Glass Industries Limited (NFGIL), and M/s Nasir Glass Industries Limited (NGIL) has been determined considering them as one single entity and attributed one single dumping margin.

Dumping Margin Table

43. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Subject countries	Producer	Normal Value/ CNV (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
Bangladesh	Nasir Float Glass Industries Ltd.	***	***	***	***	30-40
	Nasir Glass Industries Ltd.					
	Others	***	***	***	***	30-40
Thailand	All Producers	***	***	***	***	70-80

44. The Authority notes that the dumping margin from the subject countries is not only more than *de-minimus* but also significant.

G. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions by the domestic industry

45. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced below:
- a. The landed value of the subject goods from the subject countries is substantially lower as compared to the cost and the selling price of the domestic industry. This has resulted in significant positive price underselling and price undercutting, resulting in losses. This also shows the nexus between the injury suffered by the domestic industry and the imports from the subject countries.
 - b. The imports from the subject countries have increased from 64 MT in the year 2017-18 to 17362 during the POI. This increase of 17298 MT is substantially higher. Even when compared to the immediately preceding year i.e., 2018-19, the imports from the subject countries increased by 6742 MT (63%) in the POI. This substantial increase in the import quantity clearly shows the cause of injury to the domestic industry.
 - c. The imports price from the subject countries also declined in the POI as compared to the year 2018-19 and remained almost the same as compared to the year 2019-20. This shows the pressure on the domestic industry and reasons for their losses.
 - d. The dumping margins are significantly positive from the data on record, and positive price underselling and price undercutting clearly demonstrate the need for early protection from the dumped and injurious imports from the subject countries.
 - e. The exporters from the subject countries reduced their prices in order to increase their market share in the Indian market. This fact clearly establishes the price pressure on the domestic industry.
 - f. The imports from Bangladesh have taken major portion of the north-eastern market of the domestic industry. Therefore, the injury to the domestic industry in volume terms and market share is also substantial as their sales to north-eastern region declined to the extent of increase in imports from Bangladesh during the injury investigation period.
 - g. The domestic industry is still suffering losses only because of low price imports from the subject countries. It is further submitted that only because of the low priced imports, the domestic industry is not recovering its full cost despite its best efforts, the low prices import from the subject countries has created significant price pressure on the domestic industry.
 - h. The difference between the cost of sales and the selling price could not be filled due to aggressive pricing by the exporters of the subject goods from the subject countries. This has resulted in losses and negative return on capital employed.
 - i. This situation clearly depicts the price pressure on the domestic industry wherein if they don't produce the subject goods their fixed costs will increase substantially, and their losses would also increase.
 - j. As regards the applicants being habitual users of trade remedial measures, there has been resumption of dumping whenever the duty is recommended from one source or other. Given the habitual dumping by the exporters, the domestic industry cannot be barred from approaching the Authority for prevention of unfair trade practice. Further, an anti-dumping duty is to prevent unfair trade measures and not to protect the domestic industry. Hence, the imposition of an anti-dumping duty till the dumping and consequent injury thereof exists, is justified.
 - k. The exporters from Bangladesh with aggressive pricing have taken the north-eastern market from the domestic industry and therefore, the domestic industry was not able to cater to that market. On the contrary, the domestic industry has alleged that the exporters from Bangladesh are targeting eastern and north-eastern market and requested the Authority to unmask the dumping from the exporters of Bangladesh in terms of second leg of the paragraph Article 2.4.2.

- I. Non-cooperation of the exporters from Thailand and other producers from Bangladesh clearly indicate acceptance of dumping of the subject goods by the exporters.

G.2 Submissions made by the other interested parties

46. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury suffered by the domestic industry and the causal link.
 - i. Imports from the subject countries have not caused injury to the domestic industry. Further, any injury to the domestic industry during the POI is only because of COVID and not because of the imports from the subject countries.
 - ii. The domestic industry has failed to demonstrate that they are suffering injury either price or volume. It is further submitted that the volume and price related parameters show improvement over the injury investigation period. This shows that the domestic industry is doing well and there was no negative impact due to the imports from the subject countries.
 - iii. The Authority should examine if injury claimed by the domestic industry was solely due to the imports from the subject countries or was it due to reasons other than the imports from the subject countries.
 - iv. The data given by the applicants is consolidated data of 4 applicants and therefore, the interested parties are unable to comment on the individual company level data. Therefore, the interested parties requested that data of each company is provided to them for their comments. No meaningful comments can be made on consolidated data of the total applicants as a whole.
 - v. Since import data is faulty, no comments can be made in relation to price related parameters.
 - vi. The domestic industry has habitually claimed protection from imports of subject goods into India.
 - vii. The Authority should recommend reference-price based duties so that genuine exporters should not be penalized.
 - viii. The domestic industry is not supplying the subject goods in north-eastern market and therefore, the Authority should not recommend any anti-dumping duties on the subject goods.

G.3 Examination by the Authority

47. Rule 11 of the Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles*”.
48. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under:

“(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”
49. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for like products; and (b) the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the purpose

of the current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

50. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
51. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b) A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products
52. The Authority notes that:
 - a) The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.
 - b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
 - c) Cumulative assessment of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like article offered by each of them but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.
53. In view of the above, the Authority considers it is appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.
54. The Authority notes that it is not necessary that all the parameters of injury should show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or recur, in case the antidumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.
55. In relation to the submission of the interested parties that the domestic industry is not supplying the subject goods to the north-eastern market, the Authority notes that the domestic industry has indeed supplied the subject goods to the north-eastern market.
56. The Authority has taken note of various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding preceding paras *ipso facto* addresses the submissions made by the domestic industry and other interested parties.

Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry

i. Assessment of Demand/ Apparent Consumption

57. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from the DG Systems, as quantities reported in DGCI&S import data is not reflecting correct

import quantity. Demand has been determined as the sum of domestic sales of all the domestic producers and the imports from all the countries. The apparent demand/consumption of the subject goods shows a positive trend throughout the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from Bangladesh	MT	0	0	668	7583
Imports from Thailand	MT	64	1626	9952	9779
Imports from Subject countries	MT	64	1626	10620	17362
Imports from Other Countries	MT	248198	227326	197932	100692
Total Imports	MT	248,263	228,952	208,552	118,054
Domestic Sales of domestic industry	MT	875,931	1,013,390	938,950	877,327
Trend	Indexed	100	116	107	100
Sale of Other Domestic Producer		190,000	230,000	145,000	140,000
Trend	Indexed	100	121	76	74
Domestic Sales – Total		1,065,931	1,243,390	1,083,950	1,017,327
Trend	Indexed	100	117	102	95
Total Demand/Consumption	MT	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
Trend	Indexed	100	112	98	86

58. The demand of the subject goods has increased till 2018-19 and decreased thereafter till period of investigation as compared to the preceding years. It is further noted that due to pandemic, demand declined in the POI. However, domestic industry submitted that this was a short phenomenon, which will be over soon. It is further submitted by the domestic industry that increase in the import quantity from subject countries in shorter period is very substantial and considering the demand potential in India, these imports can further aggravate the injury to the domestic industry.

ii. Imports volume and share of the imports from the Subject Countries

59. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority:

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Imports from Subject countries	MT	64	1626	10620	17362
Imports from other countries	MT	248198	227326	197932	100692
Total Imports	MT	248,263	228,952	208,552	118,054
Total PUC production	MT	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
Demand of subject goods in India	MT	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
Imports from subject countries in relation to					
Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	2035	15116	27858
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	2252	16758	31188

60. It is seen that the volume of dumped imports of subject goods increased throughout the injury investigation period. It is further noted that the imports from the subject countries have increased in

the period of investigation in absolute terms as well as in relation to production, consumption and total imports.

Price effect of the Dumped Imports on the domestic industry

61. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on the domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

62. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Import Quantity from Bangladesh	MT	0	0	668	7583
Landed value from Bangladesh	Rs/MT	0	0	19376	19889
Domestic Net Sales Realization	Rs/MT	22,755	21,206	19,257	20,178
Trend	Indexed	100	93	85	89
Price Undercutting	Rs/MT	0	0	(120)	290
Trend	Indexed	0	0	(1)	1
Price Undercutting	%	0	0	(0.62)	1.46
Trend	Indexed	0	0	(100)	236
Price Undercutting	Range	0	0	Negative	0-10
Imports from Thailand	MT	64	1626	9952	9779
Landed value from Thailand	Rs/MT	16178	19716	16412	16761
Domestic Net Sales Realization	Rs/MT	22,755	21,206	19,257	20,178
Trend	Indexed	100	93	85	89
Price Undercutting	Rs/MT	6577	1490	2844	3418
Trend	Indexed	100	23	43	52
Price Undercutting	%	41	8	17	20
Trend	Indexed	100	19	43	50
Price Undercutting	Range	35-45	0-10	10-20	15-25
Import Quantity from Subject Countries	Rs/MT	64	1626	10620	17362
Landed value from subject countries	Rs/MT	16178	19716	16599	18127
Domestic Net Sales Realization	Rs/MT	22,755	21,206	19,257	20,178
Trend	Indexed	100	93	85	89
Price Undercutting	Rs/MT	6577	1490	2658	2052
Trend	Indexed	100	23	40	31
Price Undercutting	%	41	8	16	11
Trend	Indexed	100	19	39	28
Price Undercutting	Range	35-45	0-10	10-20	10-20

63. The Authority notes that the landed value of the subject goods from the subject countries is below the net sales realization of the domestic industry resulting in positive price undercutting.

ii. Price suppression/depression

64. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority considered the changes in the prices and landed value over the injury period.

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Cost of Sales	Rs/MT	20,345	21,365	20,359	21,443
Trend	Indexed	100	105	100	105
Selling Price	Rs/MT	22,755	21,206	19,257	20,178
Trend	Indexed	100	93	85	89
Landed price of Imports from subject countries	Rs/MT	16178	19716	16599	18127

65. It is seen that the cost of sales and selling price of the domestic industry declined till 2019-20 and increased in the POI whereas the landed has increased during the injury period. It is noted that the selling price of the domestic industry has remained below the cost of sales and more than the landed price of imports from the subject countries. The domestic industry has submitted that it is keeping its prices in accordance with the import price to sell their goods in the market and in that sense the imports from the subject countries have depressed the prices of the domestic industry in the POI.

Impact on economic parameters of the domestic industry

66. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Capacity, Production, sales & capacity utilization

67. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Capacity	MT	1,499,264	1,995,360	2,055,910	1,885,810
Trend	Indexed	100	133	137	126
Production – Total	MT	1,296,914	1,705,946	1,622,524	1,325,883
Trend	Indexed	100	132	125	102
Production – PUC	MT	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
Trend	Indexed	100	124	109	97
Capacity utilization based on total production	%	87	85	79	70
Trend	Indexed	100	98	91	81
Domestic sales	MT	875,931	1,013,390	938,950	877,327
Trend	Indexed	100	116	107	100

68. The capacity of the domestic industry increased till 2019-20 and thereafter declined in the POI due to closure of one of the plants during the POI. It is also noted that the production of the domestic

industry increased till 2018-19 and thereafter declined, capacity utilization of the domestic industry followed the same trend that of production. The Authority notes the submission of the domestic industry that it continued to produce at a high level of capacity in order to reduce its fixed cost. This approach allowed the company to remain afloat despite lower prices from the subject countries and other countries, the difference between cost of sales and the selling price, as shown, could not be bridged due to aggressive pricing by the exporters of the subject goods from the subject countries.

69. The domestic industry has claimed capacity as reported by the management and as per the capacity provided by the technology supplier. However, Authority has considered capacity as reported in the Pollution Control Board Certificate. Further, the production and sales of the company declined in the POI also on account of Covid pandemic.

ii. Market share

70. Market share of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Market Share	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Total Demand	MT	1,314,193	1,472,341	1,292,502	1,135,381
Trend	Indexed	100	112	98	86
Domestic Sales	%	81.11	84.45%	83.86%	89.60%
Trend	Indexed	100	104	103	110
Subject Countries	%	0.005	0.11	0.82	1.53
Trend	Indexed	100	2252	16758	31188
Other countries	%	18.89	15.44	15.31	8.87
Trend	Indexed	100	82	81	47

71. It is noted that the market share of the domestic industry increased during the injury investigation period, whereas during the same period, share of imports from the subject countries also increased.

iii. Inventories

72. Inventory with the domestic industry has been examined as below:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	150	126	86

73. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has shown increasing trend till 2019-20. However, during the POI inventory reduced, as movement of imported goods was restricted due to the global pandemic. The domestic industry however submitted that the situation is temporary, as imports will again increase post normalization of the situation.

iv. Profits, Return on Investment and Cash Profit

74. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed:

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Sales	MT	875,931	1,013,390	938,950	877,327
Trend	Indexed	100	116	107	100
Sales value	Rs. Lacs	199,322	214,898	180,814	177,027
Trend	Indexed	100	108	91	89
Selling price	Rs. /MT	22,755	21,206	19,257	20,178
Trend	Indexed	100	93	85	89
Cost	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	105	111
Cost	Rs. /MT	***	***	***	***

Particulars	UoM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Trend	Indexed	100	105	100	105
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(8)	(30)	(99)
Profit/loss per unit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(7)	(46)	(53)
Depreciation	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	110	104
Depreciation	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	100	107
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	53	36	3
Cash Profit	Rs. /MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	38	18	17
Capital employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	104	95
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(6)	(29)	(105)

75. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has been severely affected in the period of investigation. It is also noted that profit, cash profit and ROCE declined during the injury period. The profitability per MT of the domestic industry and return on capital employed, cash profit was negative in the POI.
76. The domestic industry has further submitted that due to non-remunerative prices from the subject countries the domestic industry is incurring losses and are under constant price pressure from the subject country, as price undercutting, and price underselling is significantly positive. The domestic industry also submitted that, if duties are not recommended, the situation of the domestic industry will further worsen.
77. The table above shows that the financial performance of the domestic industry has been adversely affected. This is essentially on account of the dumped and injurious imports from the subject countries coming at dumped prices due to which the domestic industry is forced to lower its prices and that has caused injury to them. Consequently, the profitability per MT of the domestic industry, return on capital employed, cash profits and profit before interest were also impacted.

v. Employment, Wages and Productivity

78. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Year	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Production	MT	1,017,204	1,261,606	1,109,105	983,836
Trend	Indexed	100	124	109	97
Employees	Nos	3,671	3,812	3,359	3,307
Trend	Indexed	100	104	92	90
Production/employee	MT/Nos	277	331	330	298
Trend	Indexed	100	119	119	107
Wages	Rs. Lacs	12,057	14,153	15,211	12,397
Trend	Indexed	100	117	126	103

Year	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	POI
Wages / Employee	Rs. / No.	328,450	371,284	452,845	374,869
Trend	Indexed	100	113	138	114

79. It is noted from the table that:

- Productivity has increased till 2019-20 and declined during the POI. The decline during the POI may be due to the COVID pandemic.
- The number of employees engaged by the domestic industry has increased till 2018-19, thereafter the number of employees and wages paid to them reduced in the POI as compared to the previous years.

vi. Magnitude of dumping

80. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India and are consequently causing injury to the domestic industry. The dumping margin from the subject countries is positive and significant.

vii. Growth

81. The parameters such as production, sales, capacity utilization, profits, profit before interest, return on capital employed, were significantly adverse.

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	POI
Production	Y/Y	24%	-12%	-11%
Capacity Utilization	Y/Y	-2%	-6%	-9%
Domestic Sales	Y/Y	16%	-7%	-7%
Cash Profit	Y/Y	-46%	-45%	-13%
Inventory	Y/Y	50%	-16%	-32%
Return on Investment	Y/Y	-7.43%	-2.88%	-0.41%

viii. Ability to raise fresh investment

82. The applicant has submitted that the profitability of the domestic industry has been adversely impacted by dumped imports in the past and considering the significant capital investment being undertaken in the country by other producers, protection against the dumped imports is necessary.

Magnitude of Injury Margin / Price underselling

83. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

84. Based on the landed price and NIP determined as above, the proposed injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

Subject countries	Producer / Exporters	NIP (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Range
-------------------	----------------------	--------------	-----------------------	------------------------	-------------------	-------

Bangladesh	Nasir Float Glass Industries Ltd.	***	***	***	***	10-20
	Nasir Glass Industries Ltd.					
	Others	***	***	***	***	10-20
Thailand	All Producers	***	***	***	***	30-40

85. It is noted that injury margin is positive and significant for cooperating producer as well as the subject countries for POI.

H. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

86. The Authority has noted other factors listed under the Rules, which could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

H.1. Non-attribution Analysis

87. The Authority holds the following with regard to the other known factors capable of causing injury to the domestic industry:

a. Imports from other sources

88. The imports of the subject goods from sources other than subject countries are below de-minimis or dumped or subject to dumping measures.

b. Contraction in demand

89. There is contraction in demand for the products under consideration in India. However, the same is due to the impact of COVID 19.

c. Changes in the pattern of consumption

90. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

91. There are no trade restrictive practice which have been brought to the notice of the Authority, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

92. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

f. Export performance

93. It is noted that the injury information examined by the Authority is for domestic operations only and therefore exports volume has not caused injury to the domestic industry.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

94. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Conclusions on injury and causal link

95. The Authority notes the following:

- Imports of the subject goods from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to consumption.
- The market share of imports of subject goods from subject countries has increased during the injury period.
- The dumped imports of subject goods from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of subject goods is below the cost of sales as well as selling

price of the domestic industry. Further, the price undercutting has led to depressing effects on the prices of the product in the market.

- d) The growth of the domestic industry became negative during the POI in terms of number of price related economic parameters like profit, return on capital employed and cash profits etc as a result of dumped imports of the subject goods from the subject countries.
- e) The volume and price effects caused by the dumped imports of subject goods from subject countries has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry during the POI. It is also noted that profit and ROCE has turned negative during the POI.

96. It is thus seen that dumped imports of subject goods from subject countries have caused material injury to the domestic industry.

I. POST-DISCLOSURE COMMENTS

Submissions of the Other Interested Parties

97. Submissions made by the other interested parties are as follows:

- a. The Authority should disclose DG Systems data. Moreover, non-disclosure of the DG System would be against the principles of natural justice and therefore, the case should be terminated.
- b. The Authority should clearly mention in the final findings that due to inherent thickness issues in the DGCIS data, the Authority has relied upon DG Systems data in the disclosure statement as well as in the final findings, as pointed out by exporters.
- c. The Authority has not properly examined the other factors affecting the performance parameters of the domestic industry. Further, the examination of other factors is also not proper.
- d. The domestic industry is not suffering any injury because of low quantum of imports from subject countries. It is submitted that the Authority should not cumulate the injury from Thailand and other countries with Bangladesh. It was further submitted that the current injury analysis is violative of Article 3.3 of the ADA.
- e. The Authority should recommend duty based on reference-based price
- f. The rejection of import volume from Bangladesh provided by the applicants in the disclosure statement clearly indicates that the evidence provided in the petition was not accurate and does not meet with the requirements of Article 5.3. This itself is a sufficient ground for termination of the investigation.
- g. The detailed injury analysis shows that there is no injury on account of the imports from Bangladesh.
- h. The Authority has admitted that there has been a contraction in demand due to impact of Covid-19 pandemic and on the other hand, the Authority has not segregated injury caused to the domestic industry due to the impact of COVID-19.
- i. The Authority must explain how a source of imports with only 0.66% and 0.86% of market share can dictate terms to domestic industry holding 77% market share.
- j. The Authority has recently imposed ADD against Malaysia. The imports from Malaysia were causing injury to the domestic industry in more than 10 months of the 12 months of POI. Thus, if there is any injury it is more likely on account of imports from Malaysia.
- k. The preference is given to goods from Bangladesh, as they are much competitive price as compared to Indian suppliers. It is further submitted that the Authority should take the cost of transportation and fuel surcharge into consideration while comparing the import prices and the domestic prices and make suitable adjustments to compare prices at the same level of trade and issue the final findings accordingly.
- l. That the Authority should confirm its margins as well as export price, normal value and landed value disclosed in the disclosure statement in the final findings.

- m. That the applicant has not provided evidence of dumping and therefore, case should be terminated. Further, the Authority has not analyzed other factors affecting dumping properly and requested to analyze the same in the final findings.
- n. That the Authority should check the excessive confidentiality claimed by the domestic industry.

Submission by the domestic industry:

98. Submissions made by the domestic industry are as follows:

- a. That the Authority should confirm the dumping margin margins in the final findings and adjust the injury margin by considering freight, as almost all the imports are concentrated in north-eastern market only. Therefore, for complete injury protection, freight adjustment in injury margin calculation is necessary in this case.
- b. That the Authority may kindly adjust the freight cost for domestic sales in north-east region while determining injury margin of the Bangladesh imports in view of the peculiar situation of the investigation. It is further submitted that this approach would be in line with the principle of fair comparison enshrined in Article 2 of the WTO Agreement.
- c. That from the disclosure statement it is clear that there is positive dumping from the subject countries causing significant material injury to the domestic industry and therefore, the Authority should recommend the anti-dumping duties at the earliest.
- d. That the low share of imports from the subject countries has no relevance whatsoever, as the relevant criteria is imports should be minimum 3% of the total imports in India. As per the settled jurisprudence, share of imports from subject countries in Demand has no relevance whatsoever.
- e. That in addition to the current injury, the Authority should also analyze the threat of further injury in order to get a complete picture of the actual and potential injury inflicted by the subject imports, as the imports post POI has increased significantly. Moreover, it is submitted by the Domestic Industry that they have witnessed around 14372 MT of imports from Bangladesh in the first four months of 2022, which is significant.
- f. That since producers in Bangladesh has sufficient freely disposable capacity and they are enhancing it further, indicates clear and imminent threat of injury and the need for and importance of protection against dumped and injurious imports from subject countries.
- g. The domestic industry has also submitted that M/s Nasir Float Glass Industries Ltd., has signed a contract with a Chinese company 'Triumph International Engineering Co., Ltd. (CTIEC). Both the additional lines are capable of producing 600 MT of the subject good per day, creating a significant addition in capacity of 4,38,000 MT per year. India, being the neighbouring country and having much higher price realization in the market, is bound to be the first-choice destination for the exporters in Bangladesh to dump the subject goods. In addition, Xinyi Glass Holdings Limited, China, which is the largest float glass manufacturer in China has announced to set-up a float glass factory by investing USD 200 million in Bangladesh.

Examination by the Authority

99. The Authority notes that some of the submissions by the domestic industry and the other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in the Final Findings. Further, the Authority has examined the additional submissions of the interested parties as under:
- a. As regards the arguments of the interested parties that the Authority failed to properly evaluate the validity of the application by the domestic industry in terms of import data, the Authority notes that the data provided in the application was reasonably sufficient for the purpose of the initiation only. Further, the interested parties have misunderstood the obligation of the Authority at the time of initiation and final findings. Thus, the Authority has rightly proceeded with the initiation on the basis of the information made available in the petition in terms of Rule 5. It is also a settled law that the final determination is required to be based on the information made available by the domestic industry as well as other interested parties after proper examination and verification by the Authority. Therefore, it is clear that the obligation of the investigating Authority at the time of

initiation and final findings are different. It is also important to note that during the process of investigation i.e., after initiation, the Authority receives responses from interested parties, and also verifies the information submitted by all the interested parties including domestic industry. Thus, the Authority goes by the verified data submitted by the exporters, domestic industry as well as other interested parties, and as such, the data initially submitted gets rectified, corrected/modified on the basis of the verification during the investigation. Since the present findings are based on duly verified information, no prejudice can be caused to any interested party.

- b. In relation to the submissions relating to violation of Article 3.3 of the ADA, it is noted that there is no violation of Article 3.3 of the ADA as the margin of dumping established in relation to the imports from each country (Bangladesh and Thailand) is more than de minimis as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible. It is further noted that the users / importers are using the subject goods produced by Domestic Industry as well as imports interchangeably. The Authority notes that since all the prescribed criteria are fully satisfied, the cumulative analysis proposed in the disclosure statement and done in the final findings is correct and fully in line with the Article 3.3 of ADA.
- c. In relation to the argument regarding the Authority using DG System data in place of DGCI&S data and its disclosure, it is noted that the exporters, during the discussions, submitted that they have exported float glass of various thicknesses under a particular invoice. However, the DGCI&S data has reported entire quantity of that invoice under one thickness head only. This, as per the submissions made by the exporters, has impacted the CIF prices of their exports to India. After analysis of DG Systems data and exporters' questionnaire response, credence was found in the request of the exporters. It is further noted that the Authority has fully disclosed the summary of the aggregate data in the disclosure statement and therefore, no prejudice can be caused to any interested parties. In addition to aforesaid, it is further noted that only after due examination of the transactions and the required analysis, DG Systems data has been relied upon for computation of the volume and value of imports to correlate quantum of exports from specified exporters and validate responses filed, to the extent feasible.
- d. Issues related to injury suffered by the domestic industry and causal link has been addressed in detail in the relevant part of the disclosure statement and also in these final findings. Since no new submissions have been provided by any of the interested parties contrary to the analysis of the Authority and therefore, the Authority confirms its injury analysis.
- e. The Authority has noted that the dumped imports from Malaysia has been causing injury to the Indian industry, however, this conclusion of the Authority does not preclude the fact that simultaneous injury is being caused by imports from Bangladesh and Thailand. The Authority holds that it is not necessary that imports from subject countries in a particular investigation, should be the sole or principal cause of injury. In view of the conclusion of the Authority that dumped imports from subject countries have caused injury to the domestic industry during the POI, the contention that the Malaysian imports had also caused injury, is of no consequence in this case.
- f. With regard to the request for reference-price based duties from participating exporter from Bangladesh as well as importers / users and their association, it is noted that the Authority has analyzed their request on the basis of the information made available and the fact and circumstances of the case, and has recommended reference price-based duties after analysing the factual matrix of the case.
- g. In relation to the submission of the domestic industry regarding analysis of threat of material injury, as imports have increased multifold post initiation of the investigation, the Authority notes that the information available on the record indicates material injury to the domestic industry on account of dumped imports of subject goods from subject countries.
- h. With regard to submission by the user/importer as well as the domestic industry about adjustment of freight in the calculations of injury margin, it is noted that injury margin has been determined as per the consistent practice of the authority in terms of the Annexure III of the Rules.
- i. With regard to the submission relating to segregating injury caused to the domestic industry due to the impact of COVID-19, it is noted that impact of COVID has been adequately addressed in the

computation of non-injurious price by adopting the principles of normalization and optimization. Further, due to the inherent nature of the product, domestic industry has no option but to keep its furnace and production operational throughout the period of investigation. It is further noted that none of the interested parties has provided any information / evidence to substantiate their submission as how the COVID has adversely impacted the operations of the domestic industry.

- j. With regard to the submission on low quantum of imports from subject countries, it is noted that imports from the subject countries are above 3% of the total imports. Further, it is noted that despite low quantum of imports, domestic industry is adversely affected by their price, and is forced to keep their prices at non remunerative levels, which is ultimately affecting their operating performance.
- k. In relation to the submissions relating to insufficient information relating to normal value, export price and dumping margin, it is noted that the information provided by the domestic industry in the application was found to be sufficient for the purpose of the initiation of the investigation in terms of Rule 5. It is also important to note that the Authority has used verified information in the final findings. Moreover, for other non-participating exporters from Bangladesh and Thailand, the Authority has used information available in terms of Rule 6(8) and therefore, no prejudice has been caused to any interested parties.

J. INDIAN INDUSTRY INTEREST & OTHER ISSUES

- 100. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by the dumping practices, prevent the decline of the domestic producers who are mostly from small and micro small segments, and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 101. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, other domestic producers, importers and consumers of the product.
- 102. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and other interested parties. ' The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations' The Authority sought information on, inter-alia interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD. Some of the imports and one association participated in the investigation. It is noted that the neither the importer nor the association has provided any relevant information regarding the impact of the anti-dumping duties. On the contrary, they have admitted that only because of price competitiveness, they are buying from subject countries. They have also requested for imposition of anti-dumping duties on reference-price mechanism, so that interest of all concerned can be protected.
- 103. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- 104. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the users have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact

of ADD on the user industry with verifiable information. Further post initiation letters from different micro level organizations supporting the investigation clearly indicates the importance of investigation for them. The impact of anti-dumping duties on end consumer will be very miniscule but it will act as catalyst in their recovery path. Thus, non-imposition of antidumping duty will adversely impact the indigenous production of the product concerned. From the information on record, it is also noted that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest. In view thereof, recommending reference price-based duties will not prejudice the commercial as well as legal interests of the interested parties including domestic industry as well as the exporters.

K. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

105. Having regard to the contentions raised, information received, submissions made and facts available before the Authority as recorded in these findings and on the basis of the determination of dumping, and consequent injury to the domestic industry made hereinabove, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration has been exported from the subject countries at a price below the normal value, thus resulting in dumping.
 - b. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry shows that the volume of imports from the subject countries have increased in absolute terms and also in relation to consumption in India.
 - c. The dumped imports of the subject goods from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of the subject goods is below the cost of sales as well as selling price of the domestic industry. Further, the price under-cutting has led to depressing effects on the prices of the product in the market.
 - d. That the volume and price effects caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries has adversely impacted the profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry during the POI. It is also noted that profit, cash profit and ROCE has turned negative during the POI.
 - e. There is causal link between dumping of the product under consideration from these subject countries and injury to the domestic industry.
 - f. The interested parties have not established the impact of ADD on the user industry with verifiable information. Since the duty recommended is based on lesser duty rule, the duty recommended is fairly reasonable and it is not likely to cause any adverse impact on the downstream industry.
 - g. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.
 - h. In terms of provisions contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Taking into account factual matrix of the case, and having regard to information provided, and submissions made by interested parties, it is considered appropriate to recommend benchmark/reference form of anti-dumping duties. The Authority recommends imposition of anti-dumping duties on import of the subject goods originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central government as the difference between the landed value of subject goods and the reference price indicated in column 7 of the table below, provided the landed value is less than the value indicated in column 7.

- i. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 88, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

Sl. No.	Sub Heading or Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Reference Price	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7005	Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000	Bangladesh	Any country including Bangladesh	Nasir Float Glass Industries Ltd.	306.10	MT	USD
2.	-do-	-do-	Bangladesh	Any country including Bangladesh	Nasir Glass Industries Ltd.	306.10	MT	USD
3.	-do-	-do-	Bangladesh	Any country including Bangladesh	Any other than S.no. 1 and 2	306.10	MT	USD
4.	-do-	-do-	Any country other than Bangladesh and Thailand	Bangladesh	Any	306.10	MT	USD
5.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any	306.10	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than Bangladesh and Thailand	Thailand	Any	306.10	MT	USD

I. FURTHER PROCEDURE

106. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Designated Authority